बहुजन हिताय! बहुजन सुखाय!

सक्षम भारत

राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक | इन्द्रजीत सिंह, मुख्य संवाददाता/सचिव, CNSI-Delhi

दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश से प्रसारित

www.sakshambharat;net, E-mail : saksham.bharat@hotmail.com

Member : CENTRAL NEWSPAPER SOCIETY OF INDIA DELHI

● वर्ष: 24 ● अंक: 22 ● नई दिल्ली ● बुधवार 29 अक्तूबर 2025 ● प्रभात कालीन ● मूल्य: 3 रूपया ● पृष्ठ: 4

रिपब्लिकन मजदूर संगठन के सदस्य बनें

E-mail : rmsdp@hotmail.com

अनागरिक गीता भारती भवन
बी-2/370, सुल्तानपुरी
दिल्ली-86

3 लाख करोड़ के कारोबार पर ब्रेक! निवेशकों में हड़कंप, इसी साल दूसरी बार रुकी एमसीएक्स पर ट्रेडिंग

बिजनेस डेस्क । मंगलवार (28 अक्टूबर 2025) को देश के सबसे बड़े कमोडिटी एक्सचेंज मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर एक बार फिर तकनीकी खामी के चलते कारोबार बाधित हो गया। सुबह बाजार खुलने से पहले ही एक्सचेंज ने निवेशकों को सूचना दी कि सिस्टम में समस्या आने के कारण फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स की ट्रेडिंग शुरू होने में देरी होगी। शुरुआत में MCX ने बताया कि कारोबार 9:00 बजे की जगह 9:30 बजे शुरू होगा लेकिन बाद में बार-बार समय आगे बढ़ाया गया। पहले 10:00 बजे, फिर 10:30 बजे तक का समय तय किया गया, पर तकनीकी गड़बड़ी दूर नहीं हो सकी।

शेयर बाजार ने बढ़त के साथ की शुरुआत; सेंसेक्स करीब 126 अंक तो निफ्टी 40 प्वाइंट चढ़ा

नई दिल्ली ।

फेडरल रिजर्व द्वारा ब्याज दरों में कटौती और अमेरिका-चीन व्यापार समझौते की संभावनाओं से प्रेरित होकर मंगलवार को शुरुआती कारोबार में शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांक सेंसेक्स और निफ्टी बढ़त के साथ कारोबार कर रहे थे। शुरुआती कारोबार में 30 शेयरों वाला बीएसई सेंसेक्स 125.93 अंक चढ़कर 84,904.77 अंक पर पहुंच गया। 50 शेयरों वाला एनएसई निफ्टी 39.8 अंक बढ़कर 26,005.85 अंक पर पहुंच गया। शुरुआती कारोबार में रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 21 पैसे गिरकर 88.40 रुपये प्रति डॉलर पर आ गया। सेंसेक्स की कंपनियों में भारतीय स्टेट बैंक, टाटा स्टील, लार्सन एंड टुब्रो, अडानी पोर्ट्स, टाइटन और मारुति प्रमुख लाभ में रहीं। वहीं आईसीआईसीआई बैंक, बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व और एशियन पेंट्स पिछड़ गए। एशियाई बाजारों में, दक्षिण कोरिया का कोस्पी और जापान का निक्केई 225 सूचकांक नीचे कारोबार कर रहे थे, जबकि शंघाई का एसएसई कम्पोजिट सूचकांक और हांगकांग का हैंग सेंग ऊपर कारोबार कर रहे थे। सोमवार को अमेरिकी बाजार सकारात्मक दायरे में बंद हुए। मेहता लिमिटेड के वरिष्ठ उपाध्यक्ष (शोध) प्रशांत तापसे ने कहा, बाजार की धारणा सकारात्मक बनी हुई है, जिसे पांच उत्प्रेरकों का समर्थन प्राप्त है अमेरिका में सीपीआई में नरमी से ब्याज दरों में कटौती की उम्मीदें बढ़ रही हैं, अमेरिका-चीन व्यापार समझौते की संभावनाएं, हाल के सत्रों में एफआईआई का प्रवाह, वॉल स्ट्रीट सूचकांकों का रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचना और दूसरी तिमाही की आय की मजबूत शुरुआत। जियोजित इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड के मुख्य निवेश रणनीतिकार वीके विजयकुमार ने कहा, नए प्रवाह से बाजार में सकारात्मक गति जारी रहने का संकेत मिलता है। टैरिफ पर अमेरिका और चीन के बीच संभावित समझौते के संकेत हैं। बाजार के लिए निकट भविष्य में सकारात्मक बात यह है कि बुधवार को होने वाली एफओएमसी (फेडरल ओपन मार्केट कमेटी) की बैठक में फेड दरों में कटौती करेगा, क्योंकि अमेरिका में सीपीआई मुद्रास्फीति (सालाना आधार पर 3 प्रतिशत) उतनी अधिक नहीं है जितनी आशंका थी। वैश्विक तेल मानक ब्रेंट क्रूड 0.05 प्रतिशत बढ़कर 65.65 डॉलर प्रति बैरल पर कारोबार कर रहा था। एक्सचेंज के आंकड़ों के अनुसार, विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफआईआई) ने सोमवार को 55.58 करोड़ रुपये के शेयर बेचे। हालांकि, घरेलू संस्थागत निवेशकों (डीआईआई) ने पिछले कारोबार में 2,492.12 करोड़ रुपये के शेयर खरीदे। सोमवार को 30 शेयरों वाला बीएसई सेंसेक्स 566.96 अंक या 0.67 प्रतिशत बढ़कर 84,778.84 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 170.90 अंक या 0.66 प्रतिशत चढ़कर 25,966.05 पर बंद हुआ।

साल के अंत तक बदल सकता है फेड का नेतृत्व, जेरोम पॉवेल की कुर्सी पर पांच दावेदार

नई दिल्ली । अमेरिका में अगले साल फेडरल रिजर्व के अध्यक्ष जेरोम पॉवेल की जगह कौन लेगा, इसे लेकर ट्रंप प्रशासन ने सस्पेंस बढ़ा दिया है। वित्त मंत्री स्कॉट बेसेन्ट ने पांच संभावित उम्मीदवारों के नामों की पुष्टि की है। एशिया यात्रा के दौरान एयर फोर्स वन में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ मीडिया से बातचीत में बेसेंट ने कहा कि वे आने वाले हफ्तों में दूसरे दौर की इंटरव्यू प्रक्रिया पूरी करेंगे और थैंक्सगिविंग के ठीक बाद ट्रंप के सामने अंतिम सूची पेश करेंगे। ट्रंप साल के अंत तक नए अध्यक्ष पर फैसला करने की उम्मीद जता चुके हैं। बेसेंट खुद फेड की नीतियों और 2008-09 की वित्तीय मंदी से लेकर महामारी के दौर तक उठाए गए कदमों के प्रखर आलोचक रहे हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि नया नेतृत्व आने पर फेड की मौद्रिक नीतियों में बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। इस बीच, ट्रंप ने सोमवार को पॉवेल पर किए गए अपने पुराने हमलों को दोहराया और आरोप लगाया कि ब्याज दरों में कटौती करने में उन्होंने देरी की। पॉवेल का जिक्र करते हुए ट्रंप ने कहा कि हमारे पास इस समय एक ऐसा व्यक्ति है, जो बिल्कुल भी समझदार नहीं है। उन्हें बहुत पहले ही ब्याज दरों में कटौती करनी चाहिए थी। उम्मीद है कि फेड बुधवार को इस साल दूसरी बार अपनी मुख्य ब्याज दरों में कटौती करेगा। अमेरिकी राष्ट्रपति इस साल के अंत तक फेडरल रिजर्व के नए चेयर का नाम तय करना चाहते हैं। यह जल्दबाजी फेड प्रमुख जेरोम पॉवेल की स्थिति से जुड़ी उन पेचीदगियों को भी दर्शाती है, जो व्हाइट हाउस के लिए चुनौती हो सकती हैं। पॉवेल का चेयरमैन कार्यकाल अगले साल मई में खत्म हो रहा है। हालांकि, वे जनवरी 2028 तक फेड के सात गवर्नरों में से एक के रूप में बोर्ड में बने रह सकते हैं। ऐसा होना दुर्लभ है, लेकिन इससे पहले भी मिसालें मौजूद हैं। अगर पॉवेल बोर्ड में रहते हैं, तो ट्रंप को कई वर्षों तक नए गवर्नर की नियुक्ति का मौका नहीं मिलेगा यानी नीति नियंत्रण के लिए कम गुंजाइश। फिर भी ट्रंप के पास एक वैकल्पिक रास्ता मौजूद है। फेड के मौजूदा गवर्नर स्टीफन मिरान, जिन्हें ट्रंप ने 16 सितंबर को नियुक्त किया था, उनकी अवधि 31 जनवरी 2026 तक है। ट्रंप पॉवेल को रिप्लेस करने के लिए अपने पसंदीदा उम्मीदवार को इसी सीट पर नामित कर सकते हैं और मई में पॉवेल के पद छोड़ने पर उसी व्यक्ति को फेड चेयर बनाया जा सकता है।

दुनिया में कार्बन उत्सर्जन रोकने से यादा जरूरी लोगों का दर्द कम करना, बोले बिल गेट्स

नई दिल्ली ।

माइक्रोसॉफ्ट के सह-संस्थापक बिल गेट्स ने कहा है कि जलवायु परिवर्तन एक गंभीर वैश्विक खतरा है, लेकिन यह सभ्यता के अंत की कहानी नहीं है। गेट्स का मानना है कि वैज्ञानिक नवाचार इस संकट को काबू करने में मदद करेगा। इसलिए दुनिया को अब अपनी जलवायु संघर्ष में रणनीतिक मोड़ लाने की जरूरत है गेट्स का कहना है कि मौजूदा दृष्टिकोण बेहद निराशावादी हो गया है, जिसमें तापमान बढ़ोतरी को रोकने के अल्पकालिक लक्ष्यों पर जरूरत से यादा ध्यान दिया जा रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन में कटौती पर इतना जोर है कि इससे गरीबी घटाने, बीमारी रोकने और गर्म हो रही दुनिया में जीवन सुधारने के लिए उठाए जाने वाले अधिक प्रभावी कदमों से संसाधन हट रहे हैं। उन्होंने कहा कि दुनिया का प्राथमिक लक्ष्य तापमान बढ़ोतरी रोकने से यादा मानव पीड़ा को कम करना होना चाहिए, खासकर गरीब देशों में रहने वाले लोगों की। गेट्स ने कहा कि अगर उन्हें विकल्प दिया जाए कि मलेरिया समाप्त किया जाए या तापमान वृद्धि को 0.1 डिग्री रोका जाए, तो वे बिना हिचक तापमान में हल्की बढ़ोतरी स्वीकार कर लेंगे। उन्होंने कहा कि लोग आज मौजूद पीड़ा को समझते ही नहीं हैं। आजकल गेट्स अपनी फाउंडेशन के लक्ष्यों पर सबसे यादा समय दे रहे हैं, जिसने स्वास्थ्य, शिक्षा और विकास पहलों में अब तक कई अरब डॉलर झोंके हैं। HIV/AIDS, टीबी और मलेरिया के खिलाफ लड़ाई में भी फाउंडेशन प्रमुख भूमिका निभा रहा है। 2015 में उन्होंने ब्रेकथ्रू एनर्जी की शुरुआत की, जिसका मकसद स्वच्छ ऊर्जा नवाचारों को तेजी से बढ़ावा देना है। गेट्स का 17 पन्नों का यह मेमो अगले महीने ब्राजील में होने वाली संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन से पहले जारी किया गया है। वह दुनिया के नेताओं से पूछना चाहते हैं कि जलवायु पर खर्च हो रहे सीमित धन को सही जगह निवेश किया जा रहा है या नहीं। गेट्स ने माना कि उनका यह संदेश विवादों को जन्म देगा। उनका कहना है कि अगर आपको लगता है जलवायु कोई बड़ी समस्या नहीं है, तो आप सहमत नहीं होंगे। अगर आप जलवायु को ही सब कुछ मानते हैं और कयामत की तरह देखते हैं, तो भी आप सहमत नहीं होंगे। मेरा दृष्टिकोण व्यवहारिक है, पैसा और नवाचार वहीं लगना चाहिए, जहां गरीब देशों की सबसे यादा मदद हो। गेट्स का यह बयान वैश्विक जलवायु नीति के फोकस को लेकर नई बहस छेड़ सकता है।

सरकारी बैंकों में 49फीसदी विदेशी निवेश की मंजूरी दे सकती है सरकार; आरबीआई से चर्चा कर रहा वित्त मंत्रालय

नई दिल्ली । सरकारी बैंकों में 49 फीसदी तक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की मंजूरी मिल सकती है। यह वर्तमान सीमा 20 फीसदी के दोगुना से भी यादा है। यह कदम सरकारी और निजी बैंकों के लिए नियमों के बीच के अंतर को कम करने के प्रयास का हिस्सा है। निजी बैंकों में एफडीआई की वर्तमान सीमा 74 फीसदी तक है। वित्त मंत्रालय कुछ महीनों से भारतीय रिजर्व बैंक के साथ इस मामले पर चर्चा कर रहा है। प्रस्ताव को अभी अंतिम रूप दिया जाना बाकी है। भारत के बैंकिंग उद्योग में विदेशी निवेशकों की दिलचस्पी बढ़ रही है। दुबई के एमिरेट्स एनबीडी ने हाल में करीब 27,000 करोड़ रुपये (3 अरब डॉलर) में आरबीएल बैंक में 60 फीसदी हिस्सेदारी खरीदने की इच्छा जताई है। जापान के सुमितोमो मित्सुई बैंकिंग कॉर्प ने करीब 17,000 करोड़ रुपये में यस बैंक में 25 फीसदी हिस्सा खरीदा है। सरकारी बैंकों में विदेशी स्वामित्व की सीमा बढ़ाने से उन्हें आने वाले वर्षों में और अधिक पूंजी हासिल करने में मदद मिलेगी। भारत की मजबूत आर्थिक वृद्धि दर पिछले तीन वित्त वर्षों में औसतन 8 फीसदी की रही है। ऋण की मांग में भी तेजी आई है। इससे देश के ऋणदाताओं का आकर्षण बढ़ा है। जनवरी से सितंबर के बीच भारत के वित्तीय क्षेत्र में सौदे 127 फीसदी बढ़कर 8 अरब डॉलर हो गए।

भारत में 12 सरकारी बैंक हैं। इनकी संयुक्त संपत्ति मार्च तक 1.71 लाख करोड़ रुपये थी। यह पूरे बैंकिंग क्षेत्र का 55 फीसदी हिस्सा है। सरकार सरकारी बैंकों में न्यूनतम 51 फीसदी हिस्सेदारी बनाए रखने की योजना बना रही है। वर्तमान में सभी 12 बैंकों में सरकार की हिस्सेदारी इससे बहुत अधिक है। कुछ में तो 90 फीसदी तक है। स्टॉक एक्सचेंजों के आंकड़ों के अनुसार, 30 सितंबर तक सरकारी बैंकों में विदेशी हिस्सेदारी केनरा बैंक में लगभग 12फीसदी से लेकर यूको बैंक में लगभग शून्य के स्तर तक है। सामान्य तौर पर सरकारी बैंकों को उनके निजी

समकक्षों की तुलना में कमजोर माना जाता है। आरबीआई ने पिछले कुछ महीनों में बैंकिंग क्षेत्र में नियमों को कम करने और आसान बनाने के लिए कई कदम उठाए हैं। साथ ही विदेशी बैंकों को भारतीय निजी ऋणदाताओं में बड़ी हिस्सेदारी रखने की अनुमति देने के लिए और अधिक खुला रुख अपनाया है। 49 फीसदी सीमा के बाद 51 फीसदी हिस्सा सरकारी बैंकों के पास रहेगा। ऐसे में बैंक पर नियंत्रण घरेलू निवेशकों का ही रहेगा। यह हिस्सेदारी छोटे और बड़े निवेशकों सहित सरकार की भी होगी। इससे विदेशी हाथों में बैंकों का नियंत्रण नहीं जाएगा। बैंकों के बोर्ड में विदेशी कंपनियों के भी अधिकारी होंगे। निवेश आने से बैंकों को विस्तार करने में मदद मिलेगी। वैश्विक स्तर पर उनकी पहुंच आसान होगा। इस खबर के बाद सोमवार के कारोबारी सत्र में निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स 3.02 फीसदी बढ़कर 8053 के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया। अंत में 2.22 फीसदी की बढ़त के साथ बंद हुआ। सरकारी बैंकों के शेयर 4.48 फीसदी तक बढ़ गए। एसबीआई का शेयर 2.08 फीसदी, पीएनबी का 2.48 फीसदी, केनरा का 2.78 फीसदी, बैंक ऑफ बड़ौदा का 2.87 फीसदी, यूनियन बैंक का 2.08 फीसदी और बैंक ऑफ इंडिया का शेयर 4.48 फीसदी चढ़कर बंद हुआ।

आरबीआई ने लौटाई जना एसएफबी की यूनिवर्सल बैंक अर्जी, शेयरों में आई करीब तीन प्रतिशत की गिरावट

नई दिल्ली । जना स्मॉल फाइनेंस बैंक को यूनिवर्सल बैंक का दर्जा पाने की कोशिश में झटका लगा है।

बैंक ने मंगलवार को बताया कि भारतीय रिजर्व बैंक ने उसकी यूनिवर्सल बैंक लाइसेंस के लिए दी गई आवेदन वापस कर दी है। किसी बैंक को यूनिवर्सल बैंक का दर्जा मिलने का मतलब है कि वह अब एक ही छत के नीचे वाणिज्यिक और निवेश बैंकिंग सहित कई तरह की वित्तीय सेवाएं प्रदान करने के लिए अधिकृत है। इसका मतलब है कि यह ग्राहकों को जमा, ऋण, निवेश बैंकिंग, संपत्ति प्रबंधन और अन्य वित्तीय समाधानों सहित सभी वित्तीय जरूरतों के लिए एक ही स्थान पर समाधान प्रदान कर सकता है। लघु वित्त बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ अजय कंवल के अनुसार, जून में दायर आवेदन को सोमवार देर शाम लौटाया गया है। हालांकि, आरबीआई ने आवेदन वापस करने के पीछे की सटीक वजहें साझा नहीं की हैं। कंवल ने कहा कि हम जल्द ही समझेंगे कि जवाब के पीछे असल कारण क्या है और नियामक की उम्मीदों के मुताबिक सुधार करेंगे। हमें यह बात ध्यान रखना होगी कि यह वापसी है, अस्वीकृति नहीं।

कंवल ने कहा कि वह इस सप्ताह के अंत में आरबीआई के शीर्ष अधिकारियों के साथ यूनिवर्सल बैंक आवेदन को वापस करने के सटीक कारणों पर चर्चा करेंगे, और बैंक द्वारा दोबारा आवेदन करने से पहले उन्हें ठीक कर लेंगे। हालांकि, उन्होंने नए आवेदन के लिए कोई समयसीमा नहीं बताई।

बैंक के संचलान पर इसका बड़ा असर नहीं पड़ेगा

उन्होंने आगे कहा है कि बैंक के वर्तमान संचालन पर इसका कोई बड़ा असर नहीं पड़ेगा। उनके मुताबिक एसेट साइड पर देखा जाए तो जाना एसएफबी को वैसे भी लगभग वही सभी गतिविधियां करने की अनुमति है, जो यूनिवर्सल बैंक करते हैं। कंवल ने स्वीकार किया कि को-लेंडिंग की सुविधा नहीं होना एक सीमितता है, पर उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि इसे बैंक अपने बिजनेस मॉडल पर किसी बड़ी बाधा के रूप में नहीं देखता।

फंडिंग कॉस्ट कम करने की योजना टली

कंवल के अनुसार, अगर यूनिवर्सल बैंक लाइसेंस मिल जाता, तो बैंक को लायबिलिटी साइड पर फायदा मिलता और फंड की लागत घटती। लेकिन अब इन योजनाओं को फिलहाल टालना पड़ेगा। उन्होंने यह भी कहा कि हाल में बैंक की पैरेंट कंपनी स्ट्रक्चर में हुए बदलाव का यूनिवर्सल बैंक बनने की आकांक्षा से कोई संबंध नहीं था।

एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक को मिली थी हरी झंडी

बता दें कि इस साल की शुरुआत में आरबीआई ने एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक को परिभाषित समयावधि के भीतर यूनिवर्सल बैंक बनने के लिए इन-प्रिंसिपल मंजूरी दी थी। जाना एसएफबी की अर्जी ने भी निवेशकों की उम्मीदें बढ़ाई थीं, जिससे इसके शेयर में तेजी देखी गई थी।

जना स्मॉल फाइनेंस बैंक के शेयरों में आई गिरावट

आरबीआई की ओर से अर्जी वापस किए जाने के बाद बैंक के शेयरों में गिरावट देखने को मिली। मंगलवार सुबह करीब 09:57 बजे बीएसई पर जाना एसएफबी का शेयर 2.79त्न गिरकर 443.95 पर कारोबार कर रहा था।

सहयोग की पहल वर्तमान डॉलर- मॉडल को डीडॉलराइजेशन की ओर ले जा रहे हैं

वैश्विक स्तरपर आज का वैश्विक आर्थिक परिदृश्य पहले से कहीं अधिक द्रुत गति से बदल रहा है। भारत, रूस, चीन, मध्यपूर्व एवं दक्षिण-एशियाई अर्थतंत्र, और अमेरिका के बीच चल रहे प्रतिस्पर्धा एवं गठबंधनों का मिजाज बदल रहा है। उस बदलते परिदृश्य में यह कहावत- सत्र प्रतीत होती है कि कल का हर कमाया तुम्हारा था, आज दामान हमारी है।ऐसे विशेष रूप से ट्रेनाल्ड ट्रम्प- रूस भारत चीन संदर्भ में प्रस्तुत किया है। अर्थात, अमेरिका-केंद्रित वैश्विक व्यवस्था का प्रभुत्व कम हो रहा है और रूस भारत चीन उस बदलाव में महत्वपूर्ण भूमिका ले रहा है, या कम-से-कम प्रयासरत है।मैं एडवोकेट किशन सनमुखदास भावनानी गोंदिया महाराष्ट्र ऐसा मानता हूं कि क्या वास्तव में रूस भारत चीन भारत ऐसे राजनीतिक कदम उठाते जा रहे हैं जिनकी गूंज व्हाइट हाउस तक पहुँच रही है,या पहुँच सकती है ऐसा अनुमान लगाया जा सकता है। दशकों से हम देखते आ रहे हैं कि वैश्विक स्तरपर पारंपरिक रूप से,वैश्विक व्यापार और ऊर्जा सौदे प्रमुख रूप से यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर में विनियोजित होते आए हैं,जिससे अमेरिका को न सिर्फ मुद्रा-चल बल्कि वैश्विक वित्त-सिस्टम में असाधारण प्रभुत्व प्रदान किया।लेकिन इस व्यवस्था में कई असंतुलन हैं,उभरती अर्थव्यवस्थाओं को डॉलर- निर्भरता के कारण विनिमय जोखिम, शुल्क- बाधाएं और नियंत्रणों का सामना करना पड़ता है। इसलिए आज हम मीडिया में उपलब्ध जानकारी के सहयोग से इस आर्टिकल के माध्यम से चर्चा करेंगे,क्या ट्रम्प की टैरिफ पॉलिसी और भारत- रूस-चीनी मुद्रा- सहयोग की पहल वर्तमान डॉलर-मॉडल को डीडॉलराइजेशन की ओर ले जा रहे हैं बता दें कि इस आर्टिकल में दिए गए विचार संकेत-तथा दिशासूचक है, न कि पूर्णतया प्रमाणित 'करार' की तरह। साथियों बात अगर हम रूस भारत चीन एवं डॉलर- सतत्मक व्यवस्था के बदलते परिदृश्य में भारत की स्थिति समझने की करें तो,सबसे पहले हम उस बड़े प्रसंग पर दृष्टि डालते हैं जिसमें डॉलर की प्रभुता और उसको चुनौती दोनों मौजूद हैं। वैश्विक रूप से डॉलर ने दशकों से मुख्य आरक्षित मुद्रा, व्यापार एवं पेट्रोलियम लेनदेन की प्रमुख मुद्रा, और अंतरराष्ट्रीय वित्तीय व्यवस्था की रीढ़ के रूप में काम किया है।लेकिन अब डीडॉलराइजेशन की दिशा में संकेत बढ़ रहे हैं- विशेष रूप से रूस-चीन-भारत जैसे देशों में जो अमेरिकी वेस्टर्न सिस्टम पर अधिक निर्भर नहीं रहना चाहते। भारत इस परिदृश्य में महत्वपूर्ण मोड़ पर है। भारत सरकार ने अपनी नीतियों में एक स्पष्ट संकेत दिया है कि भारत अपने मुद्रा-चयन, भुगतान व्यवस्था और विनिमय व्यवस्था में अधिक सक्रिय होना चाहता है,विशेष रूप से यह कि सिर्फ डॉलर के सहारे नहीं रहे। उदाहरण के लिए, रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया ने हाल में यूएई दिरहम और इंडोनेशियाई रुपिया के लिए रेफरेंस रेट फिक्स करने की घोषणा की है, जिसे रुपये के इंटरनेशनलाइजेशन की दिशा में एक कदम माना जा रहा है।इसप्रभावतः उन्होंने डॉलर प्रभुत्व को चुनौती देने की दिशा में महत्वपूर्ण रणनीतिक कदम उठाए हैं। साथियों बातें अगर हम आरबीआई द्वारा रेफरेंस-रेट्स में बदलाव,भारत की मुद्रा और व्यापार रणनीति को समझने की करें तो,आरबीआई ने यूएई व इंडोनेशिया की करेंसी के लिए रेफरेंस रेट फिक्स कर लिए हैं,इस अवसर पर यह जाना जाना महत्वपूर्ण है कि रेफरेंस रेट तय करने का क्या अर्थ है- यह उस मुद्रा के मुकाबले भारतीय रुपया का औपचारिक सार्वजनिक दर होता है, जिसे बैंक,व्यवसाय और एक्सपोर्ट- इम्पोर्ट कंपनियाँ उपयोग कर सकती हैं और जिससे विनिमय जोखिम कम होता है। यह कदम दो मायनों में रणनीतिक है:एक, यह व्यापारियों और एक्सपोर्टर- इम्पोर्टरों को डॉलर के जरिए जाने-माने मध्यस्थता (डॉलर - इंटरमीडिएशन) से बहुत हद तक मुक्त करता है। उदाहरण-स्वरूप, यदि भारत-यूएई व्यापार में दिरहम को सीधे रेफरेंस दर के तहत उपयोग कर सके, तो रुपया दिरहम या दिरहम रुपया लेनदेन आसान हो जाता है।यह मुद्रा- अंतर्राष्ट्रीयकरण की दिशा में संकेत देता है, यानी, भारत यह संदेश देना चाहता है कि रुपया सिर्फ घरेलू मुद्रा नहीं रहेगा, बल्कि व्यापारिक रूप से और वित्तीय रूप से विदेशों में अधिक स्वीकार्य हो सकेगा। साथियों बात अगर हम रूस- भारत तेल लेनदेन एवं चीनी युआन-भुगतान के पहलू को समझने की करेंगे,क्योंकि तेल खरीदी में रूस ने भारत को चीनी करेंसी युआन में भुगतान करने की सुविधा वाले इस बिंदु का विश्लेषण कुछ-यह जटिल है क्योंकि सच्चाई काफी हद तक संकेतों पर आधारित है और अभी पूर्ण रूप से स्थापित नियम नहीं दिख रहे।मीडिया स्रोत बताते हैं कि रूस-भारत के बीच तेल लेनदेन में कुछ मामलों में चीनी युआन में भुगतान की मांग हो रही है। मीडिया में ऐसी जानकारी आई है कि जुलाई 2023 में हुआ एक समाचार था कि भारतीय रिफाइनर ने कुछ रूसी क्रूड के लिए युआन में भुगतान शुरू किया है।

यानी रूस-भारत तेल लेनदेन में युआन में भुगतान मुमकिन हो रहा है और मांग हो रही है, लेकिन यह स्वीकारात्मक रूप से स्थापित सुविधा का मंच अभी पूरी तरह तैयार नहीं हुआ है और इसे रूस ने भारत को चीनी युआन भुगतान की सुविधा दे दी है के रूप में बहुत निहित रूप से नहीं कहा जा सकता। हालाँकि संकेत स्पष्ट हैं कि ऐसा एक प्रारंभिक चरण है। इसका महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि यदि ऐसा स्थायी रूप ले लेता है, तो यह डॉलर-मध्यस्थता को कम कर सकता है और भारत-रूस- चीन के आर्थिक पैटर्न को बदल सकता है, जिससे अमेरिकी डॉलर की प्रभुता पर प्रश्नचिन्ह उठ सकता है।

साथियों बात अगर हम इस साल के अंत तक पुतिन-भारत यात्रा, तेल-डिफेंस गठजोड़ एवं डॉलर पर प्रभाव को समझने की करें तो,इस वर्ष के अंत में व्लादीमिर पुतिन संभवतः भारत आ रहे हैं; तेल-डिफेंस में डील हो सकती है जिससे अमेरिका डॉलर पर प्रभाव पड़ेगा।

इस तरह का विश्लेषण वैश्विक रणनीति एवं भू-राजनीति कामिश्रण है।पहले यह देखना होगा कि क्या पुतिन की भारत यात्रा की पुष्टि हो चुकी है।यदि इस तरह का दौरा रूस-इस्टफ्राव व साझेदारी वास्तव में इस वर्ष के अंत या तदन्तर सक्रिय हो गई, तो यह अर्थ रखती है कि भारत एक भरोसेमंद रणनीतिक साझेदार बनते हुए अमेरिका-मध्यस्थ वैश्विक व्यवस्था (जिसमें डॉलर की भूमिका केंद्रीय थी) में थोड़ा- बहुत विस्थापन कर सकता है। उदाहरण के रूप में,यदि भारत- रूस मिलकर ऐसी साझेदारी करें जिनमें डॉलर का उपयोग सीमित हो, तकनीकी-प्रतिरक्षा साझेदारी बढ़े, और ऊर्जा लेनदेन गैर-डॉलर में हों, तो इसका डॉलर-मुखी व्यवस्था पर दबाव बनने का अवसर है।पर यह भी याद रखना होगा कि अमेरिका डॉलर पर असर तुरंत नहीं आएगा,वैश्विक मुद्रा व वित्त व्यवस्था बड़ी और जटिल है। हालांकि संकेत मिल रहे हैं कि बहुध्रुवीय व्यवस्था की दिशा में कदम बढ़ रहे हैं। उदाहरणस्वरूप, ब्रिक्स देशों में स्तरपर नए वित्तीय विकल्पों उपकरण पसरटीक विचार हो रहे हैं। इसलिए यदि भारत-रूस तेल- डिफेंस गठजोड़ वास्तव में रूप लेता है, तो उस कदम की गूंज अमेरिकी - व्हाइट हाउस तक पहुँच सकती है।

लेकिन इस बिंदु को घटित असर पड़ा है के रूप में नहीं बल्कि हो सकता है असर पड़े के युक्तिसूचक स्वर में लेना उचित होगा। साथियों बात अगर हम अमेरिका में ट्रम्प के टैरिफ केस और भारत -दूरगामी प्रभाव को समझने की करें तोअमेरिका में सुप्रीम कोर्ट में ट्रम्प टैरिफ पर सुनवाई होगी, लोअर कोर्ट पहले ही खारिज कर चुकी है। जैसा हमने देखा, अमेरिका का सुप्रीम कोर्ट ने 5 नवंबर को सुनवाई तय की है। निचली अदालतों (फेडरल सर्किट) ने ट्रम्प के बड़े टैरिफ- उपायों को अवैध पाया है। भारत-प्रसंग में इसका महत्व इसलिए है क्योंकि अमेरिका- केंद्रित वैश्विक व्यापार नियमों में बदलाव यदि आएँ, भारत को अवसर मिल सकता है कि वह तय कर सके अपने व्यापार मुद्राओं -भुगतान माध्यमों को पुनर्सामयोजित करे।

सम्पादकीय...

विरासत का असली वारिस

बिहार की राजनीति एक बार फिर उसी मोड़ पर है, जहां सत्ता की जड़ें वंश, विरासत और विद्रोह के ताने-बाने में उलझी हुई हैं। राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव के दो बेटे– तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव आज एक-दूसरे से अलग राहों पर खड़े हैं, लेकिन दोनों की राजनीति अब भी एक ही राजनीतिक केंद्र की परिक्रमा करती दिखती है। एक ओर राघोपुर है– जिसे लोग मुख्यमंत्रियों की धरती कहते हैं। यही वह सीट है जिसने पहले लालू प्रसाद और फिर राबड़ी देवी को सत्ता के शिखर तक पहुँचाया। अब वहीं से लालू के छोटे पुत्र तेजस्वी यादव तीसरी बार मैदान में हैं और इस बार वह सिर्फ उम्मीदवार नहीं, बल्कि 'मुख्यमंत्री पद' के दावेदार भी हैं। दूसरी ओर है महुआ– जहां कभी बड़े भाई तेज प्रताप यादव ने अपनी पहली जीत दर्ज की थी। अब वह उसी भूमि पर लौटे हैं, लेकिन इस बार पिता की पार्टी से निष्कासित होकर, एक नई राजनीतिक पहचान के साथ– जनशक्ति जनता दल के मुखिया के रूप में। देखा जाये तो यह चुनाव सिर्फ सीटों का मुकाबला नहीं, बल्कि एक परिवार के भीतर विचारों, अहं और नेतृत्व की टकराहट का भी मंच बन गया है। राघोपुर की बात करें तो आपको बता दें कि वैशाली जिले का राघोपुर विधानसभा क्षेत्र इस बार बिहार चुनाव का सबसे हाई-प्रोफाइल रणक्षेत्र बन चुका है। यहाँ के 3.4 लाख से अधिक मतदाता जानते हैं कि उनका फैसला राज्य का भविष्य तय कर सकता है। तेजस्वी यादव, महागठबंधन के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में तीसरी बार चुनाव मैदान में हैं। उनके अभियान का केंद्र है– परिवर्तन की राजनीति। रैलियों में वह बार-बार कहते हैं, यह चुनाव बिहार को दिशा देने का अवसर है, केवल सरकार बदलने का नहीं। राजद के पारंपरिक यादव वोटों के साथ इस बार वाम दलों और कांग्रेस का भी साथ है। निषाद वोटों में पकड़ रखने वाली वीआईपी पार्टी भी गठबंधन का हिस्सा है। लेकिन इस गठबंधन के लिए बड़ी चुनौती साबित हो रहे हैं भाजपा के सतीश कुमार। वही सतीश कुमार जिन्होंने 2010 में राबड़ी देवी को हराकर इस 'वीआईपी सीट' को झटका दिया था। सतीश कुमार सवाल उठाते हैं– दो बार उपमुख्यमंत्री रहे तेजस्वी अपने क्षेत्र के लिए एक कॉलेज या अस्पताल तक नहीं दिला सके। अगर स्थानीय विकास नहीं दिखा, तो राज्य के विकास के वादों पर भरोसा कैसे किया जाए तेजस्वी पर भरोसा करने वाला यादव वर्ग भी इस बार आत्ममंथन की स्थिति में है। एक ओर वह 'अपना लड़का' देख रहे हैं, तो दूसरी ओर बीते दो दशकों की सत्ता-विहीनता की कसक भी महसूस कर रहे हैं। दूसरी ओर, राघोपुर से करीब 30 किलोमीटर दूर महुआ में कहानी बिल्कुल अलग लेकिन उतनी ही भावनात्मक है। यही वह सीट है जहाँ 2015 में तेज प्रताप यादव ने अपनी पहली राजनीतिक जीत दर्ज की थी। अब वह लौटे हैं, लेकिन इस बार बिना राजद के झंडे के। महुआ में एक दिलचस्प कहावत सुनाई देती है– घी दाल में ही गिरता है। मतलब यह कि चाहे तेज प्रताप को वोट दो या राजद को, फायदा अंततः लालू परिवार को ही होगा। यह भावनात्मक रिश्ता अभी भी बिहार के यादव मतदाता के दिल में ज़िंदा है। राजद ने इस सीट पर अपने वफादार मौजूदा विधायक मुकेश रौशन को उम्मीदवार बनाया है। रौशन की सबसे बड़ी चुनौती तेज प्रताप नहीं, बल्कि भावनाएं हैं– जो लालू परिवार की हर शाखा को जोड़ती हैं। तेज प्रताप का कहना है कि राजद में लौटने से अच्छा मौत चुनना है। लेकिन बिहार के लोग जानते हैं कि इस परिवार के राजनीतिक रिश्ते हमेशा 'तलाकशुदा' नहीं होते। वे तकरार के बीच भी साथ जीने की कला जानते हैं। तेज प्रताप के वादे भी हमेशा की तरह रंगीन हैं– अगर जीत गया, तो महुआ में इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम बनाऊँगा, जहाँ भारत-पाकिस्तान मैच होगा। पर जमीनी हकीकत कुछ और है– मेडिकल कॉलेज बना, लेकिन दरवाजे बंद हैं; भवन खड़ा है, मगर बिस्तर नहीं। यही कारण है कि महुआ का मतदाता आज दिल और दिमाग के बीच झूल रहा है। इसके अलावा, बिहार की राजनीति में लालू प्रसाद यादव की विचारधारा आज दो दिशाओं में बंटती दिख रही है। तेजस्वी उस विचारधारा को आधुनिक चेहरे में ढालना चाहते हैं और अपने भाषणों में बेरोजगारी, शिक्षा और शासन की नई भाषा के बारे में बात कर रहे हैं वहीं तेज प्रताप उस विचारधारा को भावनात्मक लोकलुभावन रूप में जिंदा रखना चाहते हैं और अपने भाषणों में धर्म, जाति और गौरव के प्रतीकों का जिक्र कर रहे हैं। राघोपुर से तेजस्वी जहाँ लालू का 'विकल्प' बनने की कोशिश में हैं, वहीं महुआ में तेज प्रताप 'विरासत' के बोझ और आशीर्वाद के बीच झूलते दिख रहे हैं। बहरहाल, अब सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि इस चुनावी रणभूमि में लालू प्रसाद का आशीर्वाद ज्यादा असर दिखाता है या लालू प्रसाद का नाम। देखना दिलचस्प होगा कि पिता के समर्थन से राघोपुर में उतरा छोटा बेटा तेजस्वी यादव सत्ता की सीढ़ियाँ चढ़ता है या फिर अपने दम और अदाओं के भरोसे मैदान में उतरा बड़ा बेटा तेज प्रताप यादव कोई चमत्कार कर दिखाता है। बिहार की जनता जानती है– यहाँ राजनीति सिर्फ गणित नहीं, थोड़ा तंत्र और बहुत सारा नाट्यशास्त्र भी है। बाकी, घी दाल में गिरता है या हांडी में, यह तो मतगणना वाले दिन ही पता चलेगा।

डंकी रूट का काला सच

बेड़ियों में जकड़े युवाओं की अमेरिका से वतन वापसी की कहानियां कोई नई नहीं हैं। बस हर बार कुछ नए अध्याय जुड़ जाते हैं। ऐसे मामलों में हादसे, गिरफ्तारियां या अभियोग। हरियाणा, पंजाब, गुजरात जैसे राज्य के युवाओं की खतरनाक आकांक्षाओं को रोकने में कोई बाधा नहीं है। इतने अधिक मामले हो जाने के बावजूद जोखिमों को समझते हुए भी युवा डंकी रूट पर निकल पड़ते हैं। इस पागल दौड़ को चलाने वाली एक महत्वपूर्ण प्रेरणा अरबपति बनकर अपनी किस्मत बदलना ही है लेकिन बिना वीजा के डंकी रूट से अमेरिका पहुंचना सैंकड़ों लोगों के सपनों को बहुत महंगा पड़ता है। सपने तो टूटते ही हैं साथ ही जेल भी काटनी पड़ती है। अनेक लोगों को मौत का सामना भी करना पड़ा है। अमेरिका में पकड़े गए 25 से 40 साल की उम्र के 50 लोग अमेरिका से निर्वासित होकर लौट आए हैं। इन लोगों ने अमेरिका पहुंचने के लिए अपनी जमीनें बेच दीं, घर गिरवी रख दिए और बेहतर जिंदगी देने वाले एजैंटों पर भरोसा किया और अब वे सब कर्ज में डूब चुके हैं। हरियाणा के निर्वासित लोगों में 16 करनाल के, 14 कैथल के, 5 कुरुक्षेत्र के और एक पानीपत से है। हरियाणा के इन लोगों के अलावा पंजाब, हैदराबाद, गुजरात और गोवा के युवक भी हैं। जनवरी 2025 से अब तक लगभग 2500 भारतीय नागरिकों को अमेरिका निर्वासित कर चुका है। पश्चिमी देशों में जाने के गैर कानूनी डंकी रूट की दिल दहला देने वाली कहानियां हर बार सामने आती हैं। डंकी रूट अवैध प्रवासियों के लिए बहुत खतरनाक रास्ता है। जहां सुरक्षा की गारंटी बहुत कम होती है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सख्त नीतियों के चलते यह रूट अब युद्ध क्षेत्र जैसा हो गया है। इस तरह की घटनाएं अक्सर राजभर में रिपोर्ट की जाती हैं जिससे जांचकर्ता वीजा एजैंटों, बिचौलियों और सूत्रधारों (मानव तस्करी के दायरे में 'डंकर') का पीछा करते हैं जो कई देशों में परिष्कृत कार्टेल के भीतर काम करते हैं। सितंबर 2023 के लिए यूनाइटेड स्टेट्स कस्टम्स एंड बॉर्डर प्रोटेक्शन (यूएससीबीपी) के डेटा से पता चलता है कि 2019-20 से भारतीय अवैध प्रवासियों में पांच गुना वृद्धि हुई है। अक्तूबर 2022 और सितंबर 2023 के बीच 96,917 लोगों को पकड़ा गया, जबकि 2019-20 में यह संख्या 19,883 थी। इन आंकड़ों से भी दुस्साहसी लोगों की मुसीबतों का अनुमान नहीं लगाया जा सकता। भारतीय सिनेमा भी इन मुसीबतों का मामूली हिस्सा ही दिखला पाया है। माल्टा नौका कांड की पीड़ा को परिवार आज तक झेल रहे हैं।

जिनके बच्चे समुद्र की लहरों में बह गए और अदालतों के चक्कर में पूरा केस ही छिन्न-भिन्न हो गया और उन्हें आज तक न्याय नहीं मिला। 3 साल पहले गुजरात के दो परिवार कनाडा से अमेरिका में घुसने की कोशिश में मारे गए, जिनमें एक तीन साल का बच्चा भी था। बर्फीले तूफान में उनकी मौत ने कठोर से कठोर दिलों को भी झकझोर कर रख दिया। इसके बावजूद युवाओं में विदेश जाने की ललक कम नहीं हुई। एक रिपोर्ट बताती है कि डंकी रूट से अमेरिका जाने वाले 10 से 12 प्रतिशत लोग या तो कुदरती मुश्किलों को झेलते हुए मर जाते हैं या फिर रास्ते में ही माफिया के हाथों मारे जाते हैं। मानव तस्कर अवैध प्रवासियों को अमेरिका ले जाने के लिए प्रति व्यक्ति लगभग 50 हजार से 1 लाख डॉलर (40 लाख से 80 लाख रुपये) वसूलते हैं। शाहरुख खान की फिल्म 'डंकी' भी इसी 'डंकी रूट' पर बेस्ड थी। जिसे हजारों भारतीय हर साल अमेरिका, ब्रिटेन या किसी दूसरे यूरोपीय देश पहुंचने के लिए अपनाते हैं। यह रूट कई देशों से होकर गुजरता है। जिनमें पनामा, कोस्टा रिका, अल साल्वाडोर और ग्वाटेमाला जैसे मध्य अमेरिकी देश शामिल हैं। यहां भारतीय नागरिकों को आसानी से वीजा मिल जाता है। मैक्सिको और दक्षिण अमेरिका के बीच में स्थित ये देश मैक्सिको के रास्ते अमेरिका में घुसने वाले अवैध प्रवासियों के लिए एंट्री गेट के तौर पर काम करते हैं। इस खतरनाक यात्रा में दो साल तक का समय लग जाता है। और इसमें कई जोखिम भी शामिल हैं। जिनमें डकैती, गंभीर चोटें, महिलाओं के साथ रेप और आपराधिक गिरोहों के हाथों मौत भी शामिल है। अमेरिका-मैक्सिको सीमा पर प्रवासी महिलाओं और लड़कियों को बड़े पैमाने पर यौन हमलों का सामना करना पड़ता है। अक्सर इन घटनाओं को रिपोर्ट नहीं किया जाता और इसमें शामिल आरोपियों को कोई सजा भी नहीं मिलती। यह अवैध प्रवासियों के लिए अमेरिका पहुंचने के लिए एकमात्र रास्ता नहीं है। यह प्रवासी कनाडा के रास्ते भी अमेरिका में घुसते हैं। इसके अलावा भारतीय ब्राजील को भी अमेरिका पहुंचने के लिए ट्रांसिट रूट की तरह इस्तेमाल करते हैं। विदेश जाने के जुनून के मूल में समाज में जड़े जमाए बैठी सामाजिक बुराइयां भी कम नहीं हैं। फर्जी एजैंट इसी पागलपन का फायदा उठाकर अरबों रुपए का सिंडिकेट चला रहे हैं। लोगों को इस बात का अहसास होना चाहिए कि विदेश जाना है तो केवल कानूनी तरीकों से ही जाएं। एजैंटों को भुगतान करने से पहले उनकी जांच कर लें। उनके झूठे वादों में न फंसें। अवैध प्रवास जीवन तो बर्बाद करता ही है इससे भारतीय भी बदनाम हो रहे हैं। भारतीयों की छवि पर आंच आने से विदेश में वैध तरीके से गए भारतीयों को भी संदेह की दृष्टि से देखा जाता है क्योंकि वहां के समाज में गलत संदेश पहुंच चुका है। डंकी रूट महत्वकांक्षाओं और मुसीबत का जटिल मिश्रण है। हैरानी की बात तो यह है कि इतने हादसे होने के बावजूद जान की कीमत पर भी युवा पीढ़ी डंकी रूट अपनाने के लिए तैयार हो जाती है।

अब जूनागढ़ पर भी पाक का नापाक दावा

अपने ही क्षेत्र वाले प्रदेश भले ही न संभाल पा रहे हों, पाक अब भी पूर्व भारतीय रियासत जूनागढ़ को अपने देश का अंग मानता है। वर्ष 2020 में प्रकाशित अपने सरकारी नक्शों में पाकिस्तान ने जूनागढ़ को एक क्षेत्र ही दर्शाया है। वहां की सरकार का दावा है कि जूनागढ़ के नवाब ने लिखित रूप में वर्ष 1947 में पाकिस्तान के साथ विलय के दस्तावेज पाक-शासकों को सौंप दिए थे। मगर पाकिस्तान की सरकार जूनागढ़ के 'नवाबी परिवार' को अभी तक नाममात्र का ही सही, राजकीय सम्मान देती है, मगर कोई मदद नहीं करती। कराची स्थित 'जूनागढ़ हाउस' के वर्तमान मालिक अपनी पुरानी जमा पूंजी पर अपना शाही खर्च चला रहे हैं। वहां अब भी जूनागढ़ का पुराना शाही झण्डा फहराता है। इधर, भारतीय गुजरात के जिले जूनागढ़ की पुरानी गाथाएं अभी भी चर्चा में बनी हुई हैं। हैदराबाद, कश्मीर के अलावा जूनागढ़ की रियासत ही ऐसी थी जो विभाजन के दिनों में सर्वाधिक चर्चा में उभरी थी। संयोगवश जूनागढ़ उसी राज्य की एक स्वतंत्र इकाई है जिसने इस देश को गांधी, जिन्ना व पटेल सरीखी शख्सियतें दीं। इस रियासत के अंतिम नवाब महाबत खांजी (तृतीय) के किस्से, विभाजन के 76 वर्ष बाद भी चर्चा में बने हुए हैं। जूनागढ़ के शाही परिवार के वंशज अब भी कराची स्थित 'जूनागढ़ हाउस' में बसे हैं और वहां से भी शाही परिवार के किस्से-कहानियां अभी भी छन-छन कर बाहर आते हैं। भारतीय संदर्भ में उस अंतिम नवाब के 800 पालतू कुत्तों की कहानियां अधिक प्रचलित हैं। प्राप्त विवरणों के अनुसार इन 800 पालतू कुत्तों में प्रत्येक को एक निजी सेवादार भी उपलब्ध कराया गया और अब कुछ इतिहासकारों का यह भी कहना है कि उन शाही कुत्तों में से अगर किसी की भी मृत्यु होती तो उसके शोक में राजकीय झण्डा भी उसके अंतिम संस्कार तक झुका दिया जाता। इसी संदर्भ में इसी नवाब के शासनकाल में उनकी पालतू कुतिया रोशना और एक ब्रिटिश लैब्राडार बॉबी के विवाह की भी चर्चा होती है। रोशना को विवाह वाले दिन सोने-चांदी के आभूषणों से सजाया गया और चांदी की पालकी में विवाह स्थल पर ले जाया गया। दूसरी ओर ब्रिटिश लैब्राडार 'बॉबी' भी स्वर्णाभूषणों से लदे थे। दोनों को एक सजित शाही हाथी के हौदे पर बैठाया गया। सारी रस्में हिन्दू शाही पुजारियों ने अदा कीं। मंत्रोच्चार भी हुआ। रोशना और बॉबी की समझ के दायरे से यह सब कुछ बाहर था। इस अवसर पर आयोजित भोज पर 60 हजार पौंड के खर्च की अदायगी शाही खजाने की बहियों में दर्ज है। बाद में कुछ तत्कालीन शाही इतिहासकारों ने इसे अलग ढंग से बयान किया। उनके अनुसार यह मात्र एक रस्म थी जो किसी भी शाही शादी से पहले वास्तविक दुल्हा-दुल्हन की नजर उतारने के लिए दो कुत्तों की शादी से अदा होती थी। मगर रस्म के बाद सभी आभूषण शाही खजाने में जमा हो जाते थे। ऐसी रस्मों की पुष्टि एवं आंशिक उल्लेख करने वालों में जूनागढ़ के एक इतिहासज्ञ प्रद्युम्न खचर, भारतीय राजदरबारों के संस्मरणों पर लिखने वाले दीवान जरमनी दास और श्रीनाथ राघवन आदि भी शामिल थे।

नया सैन्य गठजोड़ भारत के लिये चुनौती

ललित गर्ग।

हाल ही में पाकिस्तान समेत संयुक्त अरब अमीरात, कतर और अजरबैजान के बीच बन रहे सैन्य गठजोड़ की खबरें भारत के लिए गंभीर चिंता का विषय हैं। यह घटनाक्रम न केवल दक्षिण एशिया बल्कि मध्य एशिया और खाड़ी क्षेत्र के भू-राजनीतिक समीकरणों को भी प्रभावित कर रहा है। पाकिस्तान लगातार अपनी रक्षा और कूटनीतिक स्थिति को मजबूत करने की दिशा में सक्रिय हुआ है और वह ऐसे देशों से निकटता बढ़ा रहा है जो भारत के रणनीतिक हितों के लिए चुनौती बन सकते हैं। भारत को इस नए उभरते गठजोड़ को केवल एक सामान्य रक्षा समझौते के रूप में नहीं देखना चाहिए, बल्कि इसे एक दीर्घकालिक रणनीतिक प्रयास के रूप में समझना चाहिए, जिसका उद्देश्य पाकिस्तान की अंतरराष्ट्रीय स्थिति को सुधारना और भारत पर अप्रत्यक्ष दबाव बनाना है। भारत को विदेश नीति और सुरक्षा के मद्देनजर इस तरह के गठबंधन बड़ी चुनौती के लिहाज देखे जाने चाहिए। पिछले महीने पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच हुए ऐतिहासिक सैन्य समझौते, जिसके तहत एक देश पर हुआ हमला दूसरे देश पर भी माना जाएगा, की तर्ज पर ही इस सैन्य गठजोड़ का विचार सामने लाया गया है। हालांकि इन चार देशों के बीच अभी कोई औपचारिक समझौता नहीं हुआ है, लेकिन माना जा रहा है कि अगले कुछ महीनों में इसकी घोषणा हो जाएगी। गौरतलब है कि तुर्किये, पाकिस्तान और अजरबैजान का त्रिपक्षीय गठबंधन, जिसे थ्री ब्रदर्स के नाम से जाना जाता है, एक मजबूत सैन्य साझेदारी का रूप ले चुका इसके अतिरिक्त, इस्लामिक मिलिट्री काउंटर टेररिज्म कोएलिशन (आईएमसीटीसी) भी है, जिसका संस्थापक सऊदी अरब है और जिसमें चालीस से अधिक सदस्य देश शामिल हैं। इन देशों के बीच सैन्य अभ्यास, हथियार सौदे और कश्मीर जैसे मुद्दों पर इनका स्वाभाविक सामूहिक रुख भारत के लिए चिंता का विषय रहा है। इससे पाकिस्तान अपनी कुचालों का जायज ठहराने एवं अपनी रक्षा की गुहार लगाते हुए भारत पर दबाव बनाना चाहता है। नहीं भूलना चाहिए कि पहलगाम आतंकी हमले के बाद जब भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया, तब ज्यादातर मुस्लिम देशों ने तटस्थ रुख अपनाया था, लेकिन तुर्किये और अजरबैजान

> **इस सैन्य गठजोड़ के हकीकत बनने की सूरत में भारत के लिए जरूरी होगा कि वह आर्मेनिया, ग्रीस और साइप्रस के साथ अपने संबंध मजबूत करे और यूएई के साथ भी द्विपक्षीय रिश्तों को और प्रगाढ़ बनाए, जो भारत का बड़ा व्यापारिक भागीदार रहा है और आम तौर पर इस्लामिक मुद्दों पर तटस्थ रुख रखता है।आज भारत को यह मानना होगा कि सुरक्षा अब केवल हथियारों का मामला नहीं है, यह अर्थव्यवस्था, कूटनीति, और तकनीक का समन्वित प्रश्न बन चुका है।**

दो ऐसे मुल्क थे, जो पूरी तरह से पाकिस्तान के समर्थन में खड़े थे। दरअसल, तुर्किये के राष्ट्रपति तैयब अर्दोआन की इस्लामिक दुनिया के मॉडर्न खलीफा बनने की सनक का पाकिस्तान समर्थन करता है, इसी वजह से तुर्किये ने संयुक्त राष्ट्र में भी कश्मीर पर पाकिस्तान के रुख का खुला समर्थन किया है। सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच हुआ हालिया रक्षा समझौता इस बात का संकेत है कि पाकिस्तान अब अपनी सुरक्षा रणनीति को क्षेत्रीय स्तर पर फैलाने में सफल हो रहा है। यह समझौता इस सिद्धांत पर आधारित है कि अगर किसी एक देश पर हमला होता है तो दोनों की संयुक्त प्रतिक्रिया होगी। यह बात भारत के लिए सीधे तौर पर खतरे की घंटी है क्योंकि इससे पाकिस्तान को रक्षा सहायता, प्रशिक्षण, संसाधन और राजनीतिक समर्थन प्राप्त हो सकता है। इसी तरह पाकिस्तान अज़रबैजान, यूएई और कतर जैसे देशों के साथ भी अपने संबंधों को मजबूत करने में जुटा है। इन देशों के साथ पाकिस्तान का यह बढ़ता सामरिक सहयोग उसके लिए आर्थिक और तकनीकी लाभ भी लेकर आ सकता है, जिससे भारत के लिए क्षेत्रीय संतुलन बनाए रखना कठिन हो सकता है। भारत को इन परिस्थितियों में अपनी विदेश नीति को अधिक सशक्त और लचीला बनाना होगा। अब वह समय बीत चुका है जब भारत केवल पारंपरिक प्रतिद्वंद्विता और सीमित क्षेत्रीय चिंताओं के आधार पर नीति बनाता था। आज की दुनिया में भू-राजनीति बहुस्तरीय हो चुकी है, जहां आर्थिक संबंध, तकनीकी साझेदारी और रक्षा सहयोग एक-दूसरे से गहराई से जुड़े हुए हैं। भारत को चाहिए कि वह अपने खाड़ी देशों से संबंधों को और सुदृढ़ करे। यूएई और सऊदी अरब जैसे देशों के साथ भारत के आर्थिक और सांस्कृतिक संबंध पहले से ही मजबूत हैं, पर उन्हें रक्षा सहयोग के स्तर पर भी विस्तारित करने की जरूरत है। भारत यदि इन देशों के साथ रणनीतिक साझेदारी बढ़ाता है तो पाकिस्तान को क्षेत्रीय स्तर पर अलग-थलग करने में मदद मिल सकती है। साथ ही भारत को यह भी समझना होगा कि पाकिस्तान केवल सैन्य ताकत पर नहीं, बल्कि कूटनीतिक चालों और मीडिया नैरेटिव के माध्यम से भी अपनी स्थिति को मजबूत करने का प्रयास कर रहा है। ऐसे में भारत को न केवल रक्षा मोर्चे पर बल्कि कूटनीतिक और सूचनात्मक मोर्चे पर भी सक्रिय रहना होगा। भारत की नीति प्रतिक्रियात्मक न होकर सक्रिय, दूरगामी और आदर्शी होनी चाहिए। भारत को यह दिखाना होगा कि वह केवल अपनी सीमाओं की रक्षा तक सीमित नहीं है, बल्कि क्षेत्रीय स्थिरता और वैश्विक शांति का भी एक भरोसेमंद संरक्षक है। भारत ही दुनिया से आतंकवाद को समाप्त करने की मुहिम छेड़े हुए है। भारत के लिए यह भी जरूरी है कि वह अपने मित्र देशों के साथ सामूहिक सुरक्षा दृष्टिकोण विकसित करे। जिस तरह अमेरिका और यूरोपीय संघ सामूहिक रक्षा नीति पर चलते हैं, उसी तरह भारत को भी इंडो-पैसिफिक क्षेत्र, एसोसिएशन ऑफ साउथईस्ट एशियन नेशनस् -देशों और मध्य पूर्व में सहयोगी नेटवर्क को सुदृढ़ करना चाहिए। यह केवल सैन्य दृष्टि से नहीं बल्कि कूटनीतिक और आर्थिक दृष्टि से भी भारत की स्थिति को मजबूत करेगा। पाकिस्तान की नई विदेश नीति की दिशा साफ है- वह भारत को घेरने की कोशिश कर रहा है, चाहे वह चीन के साथ सीपेक परियोजना के माध्यम से हो या अब मध्य-पूर्व के देशों के साथ रक्षा सहयोग के जरिए। भारत को इस घेराबंदी को तोड़ने के लिए तीन दिशा में एक साथ काम करना होगा-अपनी रक्षा क्षमता को आधुनिक बनाना, विदेश नीति में सक्रियता लाना, और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत की सकारात्मक छवि को और प्रखर बनाना। यह स्थिति भारत के लिए केवल एक चुनौती नहीं बल्कि अपनी सामरिक दूरदर्शिता को सिद्ध करने का अवसर भी है। भारत यदि समय रहते अपने पड़ोस में बढ़ते इस सैन्य गठजोड़ की गंभीरता को समझ लेता है और सक्रिय कदम उठाता है, तो वह न केवल पाकिस्तान की कूटनीतिक चालों को निष्प्रभावी बना सकता है, बल्कि दक्षिण एशिया को स्थिरता और सहयोग के नए मॉडल के रूप में प्रस्तुत कर सकता है। इन चार राष्ट्रों का सैन्य गठबंधन भारत के लिए एक चेतावनी है कि भू-राजनीति में देशों के बीच धार्मिक एकजुटता नए रूप में सामने आ रही है, ऐसे में क्षेत्रीय शांति और सुरक्षा बनी रहे, इसके लिए भारत को अपनी रक्षा क्षमताओं को मजबूत करते हुए कूटनीतिक मोर्चे पर भी सक्रिय बने रहना होगा। भारत पिछले कई वर्षों से पाकिस्तान, तुर्की और अजरबैजान को काउंटर करने के लिए अलग-अलग रणनीतियों पर काम कर रहा है। इनमें इन तीनों देशों के दुश्मनों की मदद से लेकर इन्हें आर्थिक तरीके से चोट पहुंचाना भी शामिल है। पाकिस्तान के खिलाफ भारत के कदमों से हर कोई परिचित है। अब बात करते हैं तुर्की की। भारत ने तुर्की को काउंटर करने के लिए, उसके सबसे बड़े दुश्मन ग्रीस के साथ रक्षा संबंधों को मजबूत किया है। इसके अलावा भारत ने साइप्रस के मुद्दे को भी अंतरराष्ट्रीय मंचों पर उठाना शुरू किया है, जिसकी जमीन पर तुर्की ने अवैध रूप पर कब्जा जमाया हुआ है। वहीं, भारत ने तुर्की को अपने बाजार में प्रवेश को लेकर भी सख्तियां बरती हैं।

इस सैन्य गठजोड़ के हकीकत बनने की सूरत में भारत के लिए जरूरी होगा कि वह आर्मेनिया, ग्रीस और साइप्रस के साथ अपने संबंध मजबूत करे और यूएई के साथ भी द्विपक्षीय रिश्तों को और प्रगाढ़ बनाए, जो भारत का बड़ा व्यापारिक भागीदार रहा है और आम तौर पर इस्लामिक मुद्दों पर तटस्थ रुख रखता है।आज भारत को यह मानना होगा कि सुरक्षा अब केवल हथियारों का मामला नहीं है; यह अर्थव्यवस्था, कूटनीति, और तकनीक का समन्वित प्रश्न बन चुका है। पाकिस्तान की नई चालें एवं कुचालें हमें केवल सतर्क रहने की नहीं, बल्कि सजग, सक्रिय और रणनीतिक रूप से एक कदम आगे रहने की प्रेरणा देती हैं। भारत यदि अपनी नीति में इस नए दृष्टिकोण को शामिल करता है, तो यह गठजोड़ उसके लिए खतरा नहीं बल्कि आत्मसुधार और आत्मसशक्तिकरण का अवसर साबित हो सकता है।

स्वामी, प्रकाशक, मुद्रक विजय कुमार शास्त्री ने बन्सल ऑफसेट प्रिन्टर्स, ए-9, साउथ पैंथलावाला एक्स. दिल्ली-33, से मुद्रित कर कार्यालय, बी-2/370, सुल्तानपुरी, दिल्ली-86 से प्रकाशित किया सम्पादक : विजय कुमार शास्त्री, मो : 09582093548 समाचार पत्र में प्रकाशित सामग्री से संपादक का सहमत होना आवश्यक नहीं विवादास्पद केवल दिल्ली कोर्ट में होंगे। (DELHIN/2019/00862)

दिल्ली के बुराड़ी और करोल बाग में क्लाउड सीडिंग का हुआ सफल परीक्षण, अब बारिश का इतंजार

नई दिल्ली । राजधानी दिल्ली में क्लाउड सीडिंग का पहला परीक्षण हो गया है। आज बुराड़ी और करोल बाग इलाके में कानपुर से आए विमान ने क्लाउड सीडिंग की। अधिकारियों ने मंगलवार को बताया कि बुराड़ी और करोल बाग इलाकों सहित दिल्ली के कुछ हिस्सों में क्लाउड-सीडिंग का पहला परीक्षण किया गया है। अब बारिश का इंतजार है। आईआईटी कानपुर ने दिल्ली के ऊपर क्लाउड-सीडिंग को सफलतापूर्वक अंजाम दिया, यह गलियारा लगभग 25 समुद्री मील लंबा और 4 समुद्री मील चौड़ा है, जिसमें सबसे बड़ी दूरी खेकड़ा और बुराड़ी के थोड़ा उत्तर के बीच तय की गई है। पहले दौर में जमीनी स्तर से लगभग 4,000 फीट की ऊंचाई पर छह फ्लेयर्स छोड़े गए, जिनकी जलने की अवधि 18.5 मिनट थी। दूसरी उड़ान ने दोपहर 3:55 बजे उड़ान भरी, जिनसे करीब 5000-6,000 फीट की ऊंचाई पर आठ फ्लेयर छोड़े। अधिकारियों के अनुसार, विमान ने कानपुर से दिल्ली के लिए उड़ान भरी और यह परीक्षण किया। वायु प्रदूषण से निपटने के लिए कृत्रिम वर्षा कराने के उद्देश्य से यह परीक्षण किया गया है। सर्दियों के महीनों में बिगड़ती वायु गुणवत्ता को कम करने की दिल्ली सरकार की व्यापक रणनीति का हिस्सा है। सरकार ने पिछले हफ्ते बुराड़ी के ऊपर एक परीक्षण उड़ान भरी थी। परीक्षण के दौरान, कृत्रिम वर्षा कराने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले सिल्वर आयोडाइड और सोडियम क्लोराइड यौगिकों की थोड़ी मात्रा विमान से छोड़ी गई। हालांकि, क्लाउड सीडिंग के लिए आमतौर पर आवश्यक 50 प्रतिशत की तुलना में 20 प्रतिशत से भी कम वायुमंडलीय नमी के कारण, वर्षा नहीं हो सकी।

15 मिनट से चार घंटे के भीतर दिल्ली में बारिश- सिरसा

पर्यावरण मंत्री मंजिंदर सिंह सिरसा ने ट्रायल को लेकर जानकारी देते हुए कहा कि आठ अग्नि फ्लेयर्स छोड़े गए। दिल्ली के आसमान में परीक्षण आधे घंटे तक चला। आगे कहा कि आईआईटी-कानपुर का कहना है कि क्लाउड-सीडिंग परीक्षण के 15 मिनट से चार घंटे के भीतर बारिश हो सकती है। दूसरा परीक्षण आज बाद में बाहरी दिल्ली में किया जाएगा। अगले कुछ दिनों में 9-10 परीक्षणों की योजना है।

क्लाउड सीडिंग से पहले पर्यावरण मंत्री का बयान

उड़ान भरने से पहले पर्यावरण मंत्री मंजिंदर सिंह सिरसा ने कहा था कि कानपुर से खास विमान आते ही यह काम शुरू हो जाएगा। अभी कानपुर में धुंध के कारण दृश्यता 2,000 मीटर है, जैसे ही 5,000 मीटर हो जाएगी, विमान उड़कर दिल्ली आएगा। सिरसा ने कहा था कि विमान आते ही आज परीक्षण हो जाएगा। मंगलवार सुबह मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आईटीओ घाट पर उगते सूरज को अर्घ्य दिया था। उनके साथ मंत्री मंजिंदर सिंह सिरसा, कपिल मिश्रा और रविंदर इंद्राज भी थे। सिरसा ने कहा था कि छठ पूजा बहुत धूमधाम से मनाई गई। बीते दिन मुख्यमंत्री ने डूबते सूर्य को प्रणाम किया, आज उगते सूर्य से दिल्ली की तरक्की की दुआ मांगी। उन्होंने आम आदमी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि आप वाले तीन दिन से नकारात्मक बातें फैला रहे हैं। उन्हें त्योहार में शामिल होना चाहिए था। छठी मइया उन्हें सद्बुद्धि दें। क्लाउड सीडिंग का मकसद यह परीक्षण दिल्ली की गंदी हवा साफ करने के लिए किया जा रहा है। इससे कृत्रिम बारिश होगी, जो प्रदूषण कम करेगी। पहले बुराड़ी में टेस्ट उड़ान हुई थी। उसमें चांदी का आयोडाइड और नमक छोड़ा गया, लेकिन हवा में नमी सिर्फ 20 फीसदी थी। इसलिए बारिश नहीं हुई। मौसम विभाग ने कहा है कि 28 से 30 अक्तूबर तक बादल अच्छे रह सकते हैं। मुख्यमंत्री गुप्ता ने कहा कि अगर मौसम ठीक रहा तो 29 अक्तूबर को दिल्ली में पहली कृत्रिम बारिश हो सकती है।

क्लाउड सीडिंग क्या है

क्लाउड सीडिंग, जिसे कृत्रिम वर्षा के नाम से भी जाना जाता है, एक ऐसी वैज्ञानिक प्रक्रिया है जिसका उद्देश्य बादलों में विशेष रसायनों का छिड़काव करके वर्षा कराना है। यह तकनीक उन क्षेत्रों के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है जहाँ प्राकृतिक रूप से वर्षा की मात्रा कम होती है। क्लाउड सीडिंग का सीधा संबंध प्रदूषण को कम करने से नहीं है, बल्कि यह अप्रत्यक्ष रूप से वायु गुणवत्ता में सुधार लाने में सहायक हो सकती है।

क्लाउड सीडिंग कैसे होती है

क्लाउड सीडिंग की प्रक्रिया में, बादलों में सिल्वर आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड या शुष्क बर्फ (ठोस कार्बन डाइऑक्साइड) जैसे रसायनों का छिड़काव किया जाता है। ये रसायन बादलों में मौजूद जलवाष्प को आकर्षित करते हैं, जिससे वे पानी की बूंदों या बर्फ के क्रिस्टल में बदल जाते हैं। जब ये बूंदें या क्रिस्टल पर्याप्त भारी हो जाते हैं, तो वे वर्षा के रूप में पृथ्वी पर गिरते हैं। इस प्रक्रिया के लिए उपयुक्त प्रकार के बादल और वायुमंडलीय परिस्थितियाँ अत्यंत आवश्यक हैं।

प्रदूषण पर अप्रत्यक्ष प्रभाव

क्लाउड सीडिंग सीधे तौर पर प्रदूषण फैलाने वाले कणों को हटाती नहीं है, लेकिन वर्षा के माध्यम से यह हवा की गुणवत्ता को बेहतर बनाने में योगदान दे सकती है। जब वर्षा होती है, तो हवा में निलंबित धूल, पराग कण और अन्य प्रदूषक कण पानी की बूंदों के साथ मिलकर नीचे गिर जाते हैं। इस प्रकार, वर्षा हवा को स्वच्छ करने का कार्य करती है। यह विशेष रूप से उन शहरों या औद्योगिक क्षेत्रों के लिए फायदेमंद हो सकता है जहाँ वायु प्रदूषण एक गंभीर समस्या है।

सीएम साहिबा ने करा दी फजीहत, सौरभ भरद्वाज ने रेखा सरकार की ली चुटकी

नई दिल्ली।

छठ पूजा को लेकर विपक्ष और सत्ता पक्ष के नेताओं के बीच पिछले कई दिनों से बयानबाजी हो रही है। ताजा मामले में आम आदमी पार्टी (आप) नेता सौरभ भरद्वाज ने मंगलवार को एक प्रेस वार्ता कर वासुदेव घाट पर प्रधानमंत्री का कार्यक्रम कैंसल होने पर रेखा सरकार की चुटकी ली है। आप नेता ने कहा, सीएम साहिबा ने प्रधानमंत्री की फजीहत करा दी! बिहार चुनाव से पहले मामला वायरल होने से नकली यमुना में पीएम की छठ पूजा का कार्यक्रम कैंसिल करना पड़ा। बीजेपी की टॉप लीडरशिप दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार से बेहद शर्मिंदा है, क्योंकि रेखा सरकार ने पूरा प्लान चौपट कर दिया और प्रधानमंत्री की फजीहत करा दी।

झूठ बोले कौआ काटे, काले कौए से डरियो- सौरभ भरद्वाज

उन्होंने आगे कहा, बीजेपी सरकार द्वारा बताए जाने वाले प्रदूषण और बेरोजगारी जैसे तमाम आंकड़ों पर अब दोबारा से बहस शुरू हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ दिनों पहले एक महिला से मिले, वहां नकली झोपड़ी बनाई गई। इससे पहले गुजरात विधानसभा चुनाव के दौरान इन्होंने

नकली क्लासरूम बना दिया था।

बीजेपी सरकार के ड्रामे और झूठ का भंडाफोड़- आप

सौरभ भरद्वाज ने कहा, पिछले कई दिनों से बीजेपी सरकार ने नकली यमुना बनाकर यह दिखाने का प्रयास किया कि हमने यमुना साफ कर दी। यह यमुना प्रधानमंत्री के फोटोशूट के लिए तैयार की गई थी, लेकिन जब इसकी पोल खुली तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना फोटोशूट कैंसिल कर दिया।

यह बताता है कि बीजेपी कितने भी झूठ बोले, लेकिन सच्चाई को छिपाया नहीं जा सकता है। आप नेता ने कहा, अब जब बीजेपी सरकार का ड्रामा और झूठ का भंडाफोड़ हो गया और प्रधानमंत्री को अपना फोटोशूट कैंसिल करना पड़ा तो बीजेपी कह रही है कि प्रधानमंत्री तो यहां आ ही नहीं रहे थे, लेकिन आज सुबह आखिरी समय तक तमाम न्यूज चैनेल पर यह खबर चली कि प्रधानमंत्री वासुदेव घाट पर छठ मनाने जायेंगे। उल्लेखनीय है कि इससे पहले यमुना के पानी और आयोजन को लेकर दोनों पक्ष के नेता एक दूसरे के विरुद्ध बयानबाजी कर रहे थे। राजनीतिक लड़ाई के बीच श्रद्धालुओं ने मंगलवार को उगते सूर्य को अर्घ्य देकर चार दिनों के व्रत का समापन किया। इसके बाद भी नेता जुबानी लड़ाई में व्यस्त हैं। इस बार चार वर्षों के बाद यमुना किनारे छठ पूजा का आयोजन किया गया। यमुना किनारे बने 17 घाटों पर लाखों श्रद्धालुओं ने सूर्य को अर्घ्य दिया। दिल्ली सरकार और भाजपा नेताओं का कहना था कि पूर्व की आप सरकार ने यमुना किनारे छठ पूजा के आयोजन पर रोक लगाई थी। भाजपा सरकार ने इस रोक को हटाकर भव्य तरीके से छठ पूजा का आयोजन किया। यमुना की सफाई के कारण लोग साफ पानी में पूजा अर्चना कर सके।

चुनाव हारने के बाद दिन में सपने देख रहे आप नेता- भाजपा

वहीं, आम आदमी पार्टी ने कुछ दिनों के लिए अधिक पानी छोड़कर यमुना को साफ रखने का भ्रम फैलाने का आरोप लगाया। आप नेताओं ने वासुदेव घाट पर प्रधानमंत्री के लिए गंगा जल डालकर अलग से घाट बनाने का आरोप लगाया था। प्रधानमंत्री के छठ पूजा घाट पर नहीं पहुंचने पर आप नेताओं ने मंगलवार को भी बयानबाजी जारी रखी। उनका आरोप है कि आप ने यमुना को साफ करने के भ्रम को उजागर किया इसलिए प्रधानमंत्री शामिल नहीं हुए। पलटवार करते हुए दिल्ली भाजपा के प्रवक्ता प्रवीण शंकर कपूर ने कहा कि चुनाव हारने के बाद आप नेता दिन में सपने देख रहे हैं।

अगर हम अपने डॉक्टरों का ध्यान नहीं रखेंगे तो समाज हमें माफ नहीं करेगा, शीर्ष कोर्ट की टिप्पणी

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि समाज न्यायपालिका को माफ नहीं करेगा, अगर वह डॉक्टरों का ख्याल नहीं रखती है और उनके साथ खड़े नहीं होती है। शीर्ष कोर्ट ने मंगलवार को एक याचिका पर फैसला सुरक्षित रखते हुए यह टिप्पणी की। याचिका निजी क्लीनिक, डिस्पेंसरी और गैर-मान्यता प्राप्त अस्पतालों में कोविड-19 से लड़ते हुए अपनी जान गंवाने वाले डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मचारियों को बीमा पॉलिसी में शामिल न करने के खिलाफ याचिका दायर की गई थी। जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस आर महादेवन की बेंच ने कहा कि सरकार को सुनिश्चित करना चाहिए कि बीमा कंपनियां वैध दावों का निपटारा करें। बेंच ने आगे कहा कि यह धारणा सही नहीं है कि निजी अस्पतालों के डॉक्टर केवल लाभ कमाने के लिए काम कर रहे थे। बेंच ने मौखिक रूप से कहा, अगर आपके अनुसार यह शर्त पूरी होती है कि वे (निजी डॉक्टर आदि) कोविड प्रतिक्रिया में थे और कोविड के कारण उनकी मृत्यु हुई, तो आपको बीमा कंपनी को भुगतान करने के लिए बाध्य करना चाहिए। केवल इसलिए कि वे सरकारी सेवा में नहीं थे और यह सोचना कि वे मुनाफा कमा रहे थे

और इसलिए बैठे थे, सही नहीं है। शीर्ष कोर्ट ने केंद्र सरकार को प्रधानमंत्री बीमा योजना के अलावा अन्य समान या समांतर योजनाओं के बारे में प्रासंगिक आंकड़े और जानकारी उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। बेंच ने कहा, हमें आंकड़ों और अन्य समांतर योजनाओं की जानकारी दीजिए जो प्रधानमंत्री बीमा योजना के अलावा उपलब्ध हैं। हम एक नियम तय करेंगे और उसके आधार पर बीमा कंपनी से दावे किए जा सकते हैं। हमारे फैसले के आधार पर बीमा कंपनी विचार करेगी और आदेश पारित करेगी। कोर्ट प्रदीप अरोड़ा और अन्य की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई कर रहा था। याचिका में बॉम्बे हाईकोर्ट के नौ मार्च 2021 के फैसले को चुनौती दी गई थी। हाईकोर्ट के फैसले में कहा गया था कि निजी अस्पताल के कर्मचारी को तब तक बीमा योजना के तहत लाभ नहीं मिल सकता, जब तक राज्य या केंद्र सरकार की ओर से उनकी सेवाएं न मांगी गई हों।

दिल्ली में एसिड अटैक की घटना झूठी! डीयू छात्रा ने ड्रामे के लिए टॉयलेट क्लीनर का इस्तेमाल किया, रेप के मामले में पिता गिरफ्तार

नई दिल्ली । दिल्ली में तीन लोगों द्वारा तेज़ाब हमले का आरोप लगाने वाली 20 वर्षीय लड़की के पिता को सोमवार को एक नाटकीय मोड़ में मुख्य आरोपी की पत्नी द्वारा दर्ज कराए गए एक अलग बलात्कार के मामले में गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने अपनी शुरुआती जाँच में यह भी पाया कि लड़की पर तेज़ाब नहीं फेंका गया था। बल्कि, उसने घर से टॉयलेट क्लीनर लिया था और उसे अपने हाथों पर डाल लिया था। जाँचकर्ताओं ने यह भी दावा किया कि छात्रा ने अपने पिता के कहने पर यह मामला गढ़ा था, जो बलात्कार की शिकायत का बदला लेना चाहता था। अपनी शिकायत में, दिल्ली विश्वविद्यालय के गैर-कॉलेजिएट महिला शिक्षा बोर्ड में नामांकित बीकॉम द्वितीय वर्ष की छात्रा ने आरोप लगाया था कि लक्ष्मीबाई कॉलेज के पास उसके एक परिचित जितेंद्र सिंह और उसके साथियों, ईशान और अरमान, जो दोनों भाई हैं, ने उस पर तेज़ाब से हमला किया था। सूत्रों ने इंडिया टुडे टीवी को बताया कि उन्होंने मुख्य आरोपी जितेंद्र को फँसाने के लिए हमले की साजिश रचने की बात कबूल की है। छात्रा के पिता, जिनकी पहचान अकील खान के रूप में हुई है, को जितेंद्र की पत्नी द्वारा उन पर यौन संबंध बनाने के लिए मजबूर करने और उसकी अश्लील तस्वीरें उसके पति के साथ साझा करने का आरोप लगाने के बाद गिरफ्तार किया गया। उसने बलात्कार की शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद प्राथमिकी दर्ज की गई। पुलिस ने कहा कि मामले से बचने के लिए, अकील और उसकी बेटी ने जितेंद्र और उसके दो साथियों - ईशान और अरमान - को अपराध में फँसाने के लिए एसिड अटैक की कहानी गढ़ी। अकील का चौंकाने वाला कबूलनामा तब आया जब पुलिस ने पहले कहा था कि जितेंद्र ने अपने दो साथियों के साथ मिलकर रविवार को उत्तरी दिल्ली के अशोक विहार में लक्ष्मीबाई कॉलेज के पास महिला पर हमला किया था। तीनों कथित तौर पर उस पर एसिड फेंकने के बाद भाग गए थे। जांचकर्ताओं के अनुसार, अकील ने स्वीकार किया कि उसने जितेंद्र की पत्नी द्वारा उसके खिलाफ बलात्कार का मामला दर्ज कराने की तैयारी के बारे में जानने के बाद हमले की योजना बनाई थी। सूत्रों के अनुसार, बदला लेने के लिए उसने जितेंद्र को एक झूठे एसिड हमले के मामले में फँसाने की साजिश रची। पुलिस ने बताया कि महिला ने शौचालय साफ करने वाला एसिड खरीदा और अपने पिता की मदद से हमले की योजना बनाई। अकील का जितेंद्र के साथियों इशान और अरमान से भी विवाद था, जिनका नाम एफआईआर में दर्ज था और जिन्हें शुरुआत में एसिड हमले के मामले में गिरफ्तार किया गया था। दिल्ली पुलिस ने बताया कि उन्हें सबसे पहले दीप चंद बंधु अस्पताल से एक फोन आया जिसमें उत्तरी दिल्ली के मुकुंदपुर की एक घायल महिला के भर्ती होने की सूचना दी गई थी। डीयू की द्वितीय वर्ष की गैर-कॉलेजिएट छात्रा ने पुलिस को बताया कि वह लक्ष्मीबाई कॉलेज में एक अतिरिक्त कक्षा के लिए गई थी, जब सुबह करीब 10 बजे यह घटना हुई। पुलिस के अनुसार, उसने शुरू में दावा किया था कि जब वह कॉलेज जा रही थी, तो जितेंद्र, ईशान और अरमान के साथ मोटरसाइकिल पर आया।

अचानक, अरमान ने ईशान से बोतल मिलने के बाद उस पर तेज़ाब फेंक दिया। छात्रा ने कहा कि उसने अपना चेहरा तो ढक लिया, लेकिन उसके दोनों हाथ जल गए। महिला ने दावा किया कि जितेंद्र उसका पीछा कर रहा था और लगभग एक महीने पहले उनके बीच तीखी बहस हुई थी। पुलिस ने बताया कि जितेंद्र और छात्रा मुकुंदपुर के रहने वाले हैं। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज का भी हवाला दिया, जिसमें जितेंद्र रविवार सुबह करोल बाग की एक भूमिगत पार्किंग में मोटरसाइकिल पर दिखाई दे रहा था। हमले में कथित तौर पर इस्तेमाल की गई मोटरसाइकिल बाद में इलाके से बरामद कर ली गई। हालाँकि, अकील के कबूलनामे के बाद जाँच में एक नाटकीय मोड़ आया, जिसमें पता चला कि जितेंद्र और उसके साथियों को जितेंद्र की पत्नी द्वारा दर्ज कराए गए बलात्कार के मामले का बदला लेने के लिए एसिड अटैक की साजिश रची गई थी। पुलिस के अनुसार, कथित एसिड अटैक से दो दिन पहले, 24 अक्टूबर को, जितेंद्र की पत्नी ने पीसीआर कॉल करके अकील द्वारा उत्पीड़न और ब्लैकमेल की शिकायत की थी। उसने आरोप लगाया कि 2021 से 2024 के बीच उसकी फैक्ट्री में काम करने के दौरान, अकील ने उसका यौन उत्पीड़न किया, जबरन शारीरिक संबंध बनाए और आपत्तिजनक तस्वीरों और वीडियो के ज़रिए उसे ब्लैकमेल किया। पुलिस ने बताया कि जितेंद्र के साथी अरमान और ईशान फिलहाल अपनी माँ शबनम के साथ आगरा में हैं और जल्द ही उनके जाँच में शामिल होने की उम्मीद है।

एसआईआर की घोषणा पर विवाद, राजनीतिक पार्टियों की आपत्ति पर भाजपा बोली- ये देशहित की हर बात के विरोधी

नई दिल्ली। चुनाव आयोग ने सोमवार को मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के दूसरे चरण का एलान कर दिया। इस चरण के तहत देश के 12 राज्यों में एसआईआर किया जाएगा। हालांकि चुनाव आयोग के एलान के बाद इस पर राजनीतिक विवाद भी शुरू हो गया है। कई राजनीतिक पार्टियों ने चुनाव आयोग की घोषणा पर सवाल खड़े किए और तमिलनाडु की सत्ताधारी डीएमके ने तो चुनाव आयोग की विश्वसनीयता पर ही सवाल उठा दिए। डीएमके के प्रवक्ता सर्वानन अन्नादुरई ने कहा कि असम में एसआईआर क्यों नहीं किया जा रहा है एसआईआर की प्रक्रिया कब से नागरिकता जांचने की प्रक्रिया बन गई है बिहार में चुनाव आयोग को कितने फर्जी या अवैध मतदाता मिले कई ऐसे सवाल है, जिनका जवाब चुनाव आयोग को देना है। डीएमके प्रवक्ता ने साल 2003 को कटऑफ साल रखने पर सवाल उठाए और पूछा कि 2003 को ही क्यों आधार बनाया गया है। इससे किसे फायदा होगा। इसे लेकर कोई स्पष्ट दिशा-निर्देश नहीं दिए गए हैं। डीएमके ने कहा कि हम देख रहे हैं कि चुनाव आयोग भाजपा के साथ मिलकर काम कर रहा है और वोट चोरी में शामिल है। चुनाव आयोग की विश्वसनीयता इस समय सबसे कम है।

केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने चुनाव आयोग द्वारा केरल और दूसरे राज्यों में मतदाता सूची गहन पुनरीक्षण करने के फैसले की कड़ी आलोचना की और इसे लोकतांत्रिक प्रक्रिया के लिए एक गंभीर चुनौती बताया। एक बयान में, उन्होंने कहा कि इस कदम से चुनाव आयोग की मंशा पर शक पैदा होता है और चेतावनी दी कि यह चुनावी व्यवस्था में लोगों के भरोसे को कम कर सकता है। विजयन ने बताया कि आयोग मौजूदा वोटर लिस्ट के बजाय 2002 से 2004 तक की वोटर लिस्ट के आधार पर रिवीजन करने की तैयारी कर रहा है, जो 1950 के रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट और 1960 के रजिस्ट्रेशन ऑफ इलेक्टर्स रूल्स का उल्लंघन होगा। उन्होंने कहा कि ये कानून साफ तौर पर कहते हैं कि कोई भी अपडेट मौजूदा वोटर लिस्ट को आधार बनाकर ही किया जाना चाहिए।

टीएमसी ने कहा- वैध मतदाता को परेशान किया गया तो हम विरोध करेंगे

पश्चिम बंगाल में भी एसआईआर की प्रक्रिया होगी। टीएमसी ने इसे लेकर कहा कि हम भी पारदर्शी मतदाता सूची के पक्ष में हैं। पूरी प्रक्रिया लोकतांत्रिक तरीके से होगी, लेकिन अगर वैध मतदाता को परेशान किया गया तो हम इसका विरोध करेंगे। राज्य सरकार, राज्य धर्म निभाएगी। हम उम्मीद करते हैं कि चुनाव आयोग राजनीतिक दबाव में ऐसा कुछ नहीं करेगा कि हमें उसका विरोध करना पड़े। वहीं पश्चिम बंगाल भाजपा ने टीएमसी के बयान पर निशाना साधा। भाजपा नेता केया घोष ने कहा कि भाजपा का मानना है कि बंगाल में कोई भी फर्जी या अवैध मतदाता नहीं होना चाहिए। ममता बनर्जी की सरकार एसआईआर से इसलिए डर रही है क्योंकि उनके वोटबैंक में रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठिए शामिल हैं।

बिहार का तेजस्वी प्रण, महागठबंधन ने जारी किया घोषणापत्र, जनता के लिए लुभावने वादों की झड़ी

पटना।

बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले महागठबंधन ने शुक्रवार को अपना साझा घोषणा पत्र जारी कर दिया। इसका नाम रखा गया है 'बिहार का तेजस्वी प्रण'। इस घोषणा पत्र में युवाओं को रोजगार, महिलाओं को सम्मान और आम लोगों को राहत देने वाले कई वादे किए गए हैं। महागठबंधन ने दावा किया है कि यह घोषणा पत्र सिर्फ चुनावी वादों का पुलिंदा नहीं, बल्कि बिहार के पुनर्निर्माण की रूपरेखा है। घोषणा पत्र जारी करने के मौके पर मंच पर राजद नेता तेजस्वी यादव, कांग्रेस के पवन खेड़ा, वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी, वाम दलों के प्रतिनिधि और अन्य सहयोगी दलों के नेता मौजूद थे। तेजस्वी यादव ने कहा यह सिर्फ हमारा घोषणापत्र नहीं, यह बिहार की जनता का प्रण है। हम इस राज्य को बेरोजगारी, पलायन और भ्रष्टाचार से मुक्त करेंगे। पवन खेड़ा ने कहा कि घोषणापत्र से स्पष्ट है कि कौन बिहार के लिए गंभीर है। कौन दिन-रात सोच रहा है। सरकार बनने के पहले दिन से क्या-क्या करना है। 20 वर्षों में जो बिहार पीछे चला गया है। उन्होंने कहा कि मैनिफेस्टो कमेटी भी बधाई की पात्र है। उन्होंने कहा कि इस मैनिफेस्टो को पावन दिन में जारी किया गया है।

20 महीने में हर घर के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने का ऐलान, 20 दिन में बनाया जाएगा अधिनियम

नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा कि महागठबंधन का चुनाव घोषणापत्र बिहार को देश का नंबर वन राज्य बनाने का विजन डॉक्यूमेंट है। हमारे पास राज्य के विकास के लिए एक विज़न और उसका रोडमैप है। बिहार को नंबर वन राज्य बनाने का हमलोगों ने प्रण लिया है।

मैनिफेस्टो में वक्फ कानून पर रोक लगाने की बात कही गई है। गरीबों को पांच सौ रुपये में गैस सिलेंडर दिया जाएगा।

शराबबंदी कानून की समीक्षा भी की जाएगी। कहा गया है कि सरकार बनने के 20 दिनों के अंदर हर परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने का अधिनियम लाया जाएगा।

20 महीने के अंदर नौकरी देने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। सभी जीविका दीदियों को स्थायी कर सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाएगा। आइटी पार्क, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, डेयरी एवं कृषि आधारित उद्योग, स्वास्थ्य सेवा, फूड प्रोसेसिंग आदि की नीति बनाई जाएगी। पुरानी पेंशन योजना लागू की जाएगी। मनरेगा की मजदूरी प्रतिदिन 255 की जगह तीन सौ रुपये किया जाएगा।

तूफान मोंथा के चलते विशाखापत्तनम एयरपोर्ट बंद, सभी उड़ानें रद्द ; 120 ट्रेनें भी हुई कैंसिल

विशाखापत्तनम।

चक्रवाती तूफान मोंथा के कारण मंगलवार को विशाखापत्तनम एयरपोर्ट से संचालित होने वाली सभी 32 फ्लाइट्स कैंसिल कर दी गईं। विशाखापत्तनम एयरपोर्ट के डायरेक्टर एन. पुरुषोत्तम ने बताया कि 27 अक्टूबर को एयर इंडिया एक्सप्रेस की दो फ्लाइट्स कैंसिल कर दी गई थीं। पुरुषोत्तम ने बताया, असल में, हम रोजाना 30 से 32 फ्लाइट्स (घरेलू और इंटरनेशनल) ऑपरेट करते हैं।

आज, वे सभी फ्लाइट्स कैंसिल कर दी गई हैं। उन्होंने आगे कहा कि एयरपोर्ट ने एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस के अनुसार, गंभीर चक्रवाती तूफान से बचने के लिए सावधानियां बरती हैं, जिसमें तूफान से पहले और तूफान के बाद के चरण शामिल हैं। इसी तरह, विजयवाड़ा एयरपोर्ट ने आज 16 फ्लाइट्स कैंसिल कर दीं, लेकिन पांच फ्लाइट्स ऑपरेट हुईं। एयरपोर्ट अथॉरिटी के अनुसार, एयरलाइंस ने आज के लिए ऑपरेशन सस्पेंड करने का फैसला किया है, और कल के फ्लाइट ऑपरेशन के बारे में शाम तक स्थिति साफ हो जाएगी। इसी तरह, तिरुपति एयरपोर्ट पर चार फ्लाइट्स कैंसिल कर दी गईं। इस बीच, एक रेलवे अधिकारी ने बताया कि साउथ सेंट्रल रेलवे जोन में 27 अक्टूबर और मंगलवार को कुल 120 ट्रेनें कैंसिल कर दी गईं। बंगाल की खाड़ी में उठा चक्रवात 'मोंथा' आज सुबह एक गंभीर चक्रवाती तूफान में तब्दील हो गया है। मौसम विभाग के अनुसार यह तूफान 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उत्तर-पश्चिम की ओर बढ़ते हुए आंध्र प्रदेश के काकीनाडा और मछलीपट्टनम के बीच तट से टकरा सकता है। इसका असर ओडिशा, तेलंगाना, झारखंड और तमिलनाडु तक महसूस किया जा सकता है इस बीच, केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने रेलवे विभाग की तैयारियों की समीक्षा की है। उन्होंने विशेष रूप से विजयवाड़ा, विशाखापट्टनम और गुंटूर डिवीजनों में आवश्यक मशीनरी, सामग्री और मानवबल तैयार रखने के निर्देश दिए हैं। रेलवे ने अपने डिविजनल वार रूम सक्रिय कर दिए हैं ताकि ट्रेन सेवाओं पर चक्रवात के प्रभाव को न्यूनतम किया जा सके। दक्षिण मध्य रेलवे और पूर्वी तटीय रेलवे ने कई ट्रेनों को रद्द या पुनर्निर्धारित कर दिया है। यात्रियों को सतर्कता बरतने की सलाह दी गई है।

इसी तरह, तिरुपति एयरपोर्ट पर चार फ्लाइट्स कैंसिल कर दी गईं। इस बीच, एक रेलवे अधिकारी ने बताया कि साउथ सेंट्रल रेलवे जोन में 27 अक्टूबर और मंगलवार को कुल 120 ट्रेनें कैंसिल कर दी गईं।

प्रशांत किशोर को चुनाव आयोग ने दिया नोटिस, 2 वोटर एनरोलमेंट पर 3 दिन में मांगा जवाब

नई दिल्ली। भारतीय चुनाव आयोग (ईसीआई) ने मंगलवार को जन सुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर को बिहार और पश्चिम बंगाल दोनों राज्यों में कथित तौर पर मतदाता के रूप में नामांकित होने के लिए नोटिस जारी किया। द इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के अनुसार, प्रशांत किशोर का नाम पश्चिम बंगाल और बिहार की मतदाता सूची में है। चुनावी रणनीतिकार से राजनेता बने किशोर, जिनकी पार्टी बिहार विधानसभा चुनाव लड़ रही है, का पता कोलकाता के 121 कालीघाट रोड पर दर्ज है, जो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भवानीपुर निर्वाचन क्षेत्र में तृणमूल कांग्रेस कार्यालय का पता है। इस रिपोर्ट का हवाला देते हुए, चुनाव आयोग ने अपने नोटिस में कहा कि किशोर का नाम निर्मल हृदय विद्यालय, बीडन स्ट्रीट, कोलकाता की मतदाता सूची में और बिहार के 209-करगहर विधानसभा क्षेत्र (भाग संख्या 767, क्रम संख्या 621) में भी मतदाता पहचान पत्र IUJ1323718 के साथ दर्ज है। चुनाव आयोग ने याद दिलाया कि जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 17 के तहत, कोई व्यक्ति एक से ज्यादा निर्वाचन क्षेत्रों में मतदाता के रूप में पंजीकृत नहीं हो सकता। इस नियम का उल्लंघन इसी अधिनियम की धारा 31 के अंतर्गत दंडनीय है। किशोर को भेजे गए नोटिस में कहा गया है, आपसे अनुरोध है कि आप एक से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों में अपना नाम दर्ज होने के संबंध में तीन दिनों के भीतर स्पष्टीकरण दें।

जयपुर में हाईटेंशन लाइन से टकराकर जल उठी बस, तीन की मौत, 12 से ज्यादा लोग झुलसे

जयपुर। जयपुर ग्रामीण जिले के शाहपुरा उपखण्ड के मनोहरपुर थाना क्षेत्र में मंगलवार सुबह बड़ा हादसा हो गया। टोडी गांव स्थित एक ईंट भट्टे पर जा रही मजदूरों से भरी बस 11 हजार वोल्ट की हाईटेंशन लाइन के संपर्क में आ गई।

पल भर में बस में तेज करंट दौड़ गया और स्पार्क होने से आग भड़क उठी। देखते ही देखते बस में सवार मजदूर करंट और आग की चपेट में आ गए। हादसे में मौके पर ही तीन मजदूरों की दर्दनाक मौत हो गई। लगभग 12 मजदूर गंभीर रूप से झुलस गए। जान गंवाने वाले तीन लोगों में दो पिता और पुत्री बताए जा रहे हैं। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार हादसे के समय बस यूपी से मजदूरों को लेकर टोडी स्थित ईंट भट्टे पर पहुंच रही थी। रास्ते में बस के ऊपरी हिस्से का हाईटेंशन लाइन से संपर्क होते ही जोरदार धमाका हुआ और तेजी से आग फैल गई। घटना के बाद वहां अफरा-तफरी मच गई। मजदूरों की चीख-पुकार सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही मनोहरपुर थाना पुलिस और प्रशासनिक टीम घटनास्थल पर पहुंची और घायलों को तुरंत शाहपुरा उपजिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर रूप से घायल पांच मजदूरों को बेहतर इलाज के लिए जयपुर रेफर किया है। दमकल विभाग की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद बस में लगी आग पर नियंत्रण पाया। पुलिस ने मृतकों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी भेज दिया है। वहीं घटना के कारणों की जांच शुरू कर दी गई है। प्रारंभिक जांच में हाईटेंशन लाइन के अत्यधिक नजदीक से बस के गुजरने को हादसे की प्रमुख वजह माना जा रहा है। प्रशासन ने ईंट भट्ठा संचालक और बस चालक की भूमिका की भी जांच के आदेश दिए हैं। एसडीएम संजीव से मिली जानकारी कि अनुसार हादसे के समय बस में 60 सवारी थीं। सभी श्रमिक हैं, जो शाहपुरा के आसपास ईंट भट्टों पर काम करते हैं। दिवाली मनाने के बाद सभी यूपी के पीलीभीत से प्राइवेट बस बुक करके काम पर लौट रहे थे। बस की छत पर कपड़े, खाने-पीने का सामान रखा था। हाईटेंशन लाइन से टच होते ही छत पर रखे लगेज ने आग पकड़ ली।

आंध्र प्रदेश के चित्तूर में दो सरकारी बसों की आमने-सामने की टक्कर, 20 घायल

आंध्र प्रदेश के चित्तूर में बड़ा हादसा हो गया। चित्तूर में मंगलवार सुबह आंध्र प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की दो बसों के बीच आमने-सामने की टक्कर हो गई, जिसमें 20 यात्री घायल हो गए। पुलिस के अनुसार, यह दुर्घटना उस समय हुई, जब बसें पुंगनूर मंडल में मोड़ लेने की कोशिश कर रही थीं। पालमनेर के पुलिस उपाधीक्षक (डीएसपी) बी प्रभाकर ने बताया, एपीएसआरटीसी की दो बसें आपस में टकरा गईं और लगभग 20 लोग घायल हो गए। किसी को गंभीर चोट नहीं आई है और मामूली रूप से घायल लोगों को नजदीकी सरकारी अस्पताल ले जाया गया है। उन्होंने बताया कि टक्कर के समय दोनों बसों में कुल 48 यात्री सवार थे।

बिहार को नंबर एक राज्य बनाने का विजन दस्तावेज होगा 'इंडिया गठबंधन का घोषणापत्र : तेजस्वी यादव

पटना। राष्ट्रीय जनता दल (राजद) नेता तेजस्वी प्रसाद यादव ने मंगलवार को कहा कि 'इंडिया गठबंधन का चुनाव घोषणापत्र बिहार को देश का नंबर एक राज्य बनाने वाला विजन दस्तावेज होगा।

विपक्षी गठबंधन 'इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इन्क्लूसिव अलायंस (इंडिया) का चुनाव घोषणापत्र आज ही दोपहर में जारी किया जाना है। तेजस्वी ने यहां पत्रकारों से कहा, हमारे पास बिहार के विकास के लिए स्पष्ट विजन और रोडमैप है। इसे 'तेजस्वी प्रण पत्र भी कहा जा सकता है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) पर हमला करते हुए उन्होंने कहा, हमने चुनाव से पहले ही मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार की घोषणा कर दी... हम आज अपना घोषणापत्र जारी करने जा रहे हैं। राजग की पार्टियों का क्या उन्होंने न तो अपने मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार की घोषणा की है और न ही घोषणापत्र जारी किया। वे तो हमारे वादों की नकल करते हैं। तेजस्वी ने यह भी आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बिहार के लिए कोई रचनात्मक कार्य नहीं किया। 'इंडिया गठबंधन की ओर से बिहार के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार तेजस्वी ने कहा, प्रधानमंत्री जब भी बिहार आते हैं... विपक्ष के नेताओं को कोसते हैं और नकारात्मक राजनीति को बढ़ावा देते हैं।

आठवें वेतन आयोग की रूपरेखा को कैबिनेट की मंजूरी, 18 महीने का कार्यकाल, 50 लाख कर्मियों को फायदा

नई दिल्ली। दिवाली और छठ पूजा के बीच केंद्र सरकार ने करोड़ों सरकारी परिवारों को खुश कर देने वाला बड़ा फैसला लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में 8वें वेतन आयोग को औपचारिक मंजूरी दे दी गई है। अब यह आयोग अगले 18 महीनों में अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपेगा, जिसके आधार पर केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों की सैलरी और पेंशन संरचना में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है।

कौन होंगे आयोग में शामिल

सरकार ने सुप्रीम कोर्ट की पूर्व जज जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई को आयोग का चेयरपर्सन नियुक्त किया है। उनके साथ IIM बेंगलुरु के प्रोफेसर पुलक घोष और पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के सचिव पंकज जैन सदस्य होंगे। यह टीम केंद्र सरकार को वेतन, भत्ते और पेंशन से जुड़ी सिफारिशें तैयार कर सौंपेगी।

कर्मचारियों और पेंशनर्स को सीधा फायदा

केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी ने आयोग की शर्तों और अधिकारों को मंजूरी दे दी है। इस निर्णय से करीब 50 लाख केंद्रीय कर्मचारी और लगभग 69 लाख पेंशनभोगी, जिनमें रक्षा सेवाओं के कर्मी भी शामिल हैं, को सीधा लाभ मिलेगा।

शाह पर टिप्पणी के बाद शिंदे का उद्धव पर पलटवार, कहा- जो दूसरों को बताते हैं, वे खुद असली एनाकोंडा

मुंबई। महाराष्ट्र की राजनीति में बयानबाजी ने एक बार फिर गरमी बढ़ा दी है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने मंगलवार को शिवसेना (यूबीटी) प्रमुख उद्धव ठाकरे पर तीखा हमला बोलते हुए उन्हें मुंबई की कोषागार पर लिपटा एनाकोंडा कहा। यह प्रतिक्रिया उद्धव ठाकरे के उस बयान के बाद आई, जिसमें उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को मुंबई को निगलने वाला एनाकोंडा कहा था। पत्रकारों से बात करते हुए शिंदे ने कहा कि जो दूसरों को एनाकोंडा बताते हैं, वे खुद असली एनाकोंडा हैं। ये लोग मुंबई की कोषागार पर लिपटे हुए है, और इनका पेट कभी नहीं भरता। शिंदे ने आगे कहा कि ठाकरे गुट ने मुंबई को लूटने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उन्होंने आरोप लगाया कि बीएमसी की कोषागार से लेकर कोविड काल की खिचड़ी तक में घोटाले हुए हैं। शिंदे ने कहा कि उन्होंने मुंबई, उसकी कोषागार, प्लॉट्स, मरीजों की खिचड़ी, शवों के बैग और यहां तक कि मिठी नदी की गाद तक को निगल लिया। इनका भ्रष्टाचार की भूख कभी खत्म नहीं होती। उन्होंने कहा कि उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में जब शिवसेना (अविभाजित) 1997 से 2022 तक लगातार 25 साल बीएमसी पर काबिज रही, तब भ्रष्टाचार का बोलबाला रहा। शिंदे ने कहा कि शिवसेना (यूबीटी) को अब जवाब देना चाहिए कि मुंबई के विकास के नाम पर उन्होंने आखिर किया क्या। ठाकरे द्वारा अमित शाह को 'एनाकोंडा' कहे जाने के बाद भाजपा ने भी तीखी प्रतिक्रिया दी। भाजपा नेता चंद्रशेखर बावनकुले ने कहा कि उद्धव ठाकरे अपने चुनावी हार से निराश हैं और इसीलिए अनर्गल बयान दे रहे हैं। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि उद्धव जी को शीशा देखकर खुद को देखना चाहिए, क्योंकि वे खुद वो एनाकोंडा हैं जो दूसरों के परिश्रम पर फुफकारते हैं।

संघ की गतिविधियों पर रोक लगाने की कर्नाटक सरकार की कोशिशों को झटका, हाईकोर्ट ने आदेश पर लगाई रोक

बंगलूरू। कर्नाटक उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को झटका देते हुए उसके एक आदेश पर रोक लगा दी है। दरअसल इस आदेश के तहत कर्नाटक सरकार ने निजी संगठनों को सरकारी परिसरों और सार्वजनिक जगहों, सड़कों आदि पर कोई भी कार्यक्रम आयोजित करने से प्रशासन की मंजूरी लेना अनिवार्य कर दिया था। कर्नाटक सरकार के इस आदेश को संघ की गतिविधियों को राज्य में बाधित करने के तौर पर देखा जा रहा था।

हालांकि अब कर्नाटक उच्च न्यायालय की धारवाड़ पीठ ने इस आदेश पर रोक लगा दी है। राज्य सरकार के आदेश के खिलाफ पुनश्चैतन्य सेवा समस्थे नामक संगठन ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी। याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस नागप्रसन्ना की एकल पीठ ने राज्य सरकार के आदेश पर अंतरिम रोक लगाते हुए मामले की सुनवाई 17 नवंबर तक टाल दी है। याचिका दायर करने वाले संगठन की तरफ से पेश हुए वरिष्ठ वकील अशोक हरनहल्ली ने सुनवाई के दौरान कहा कि राज्य सरकार का आदेश संविधान में दिए गए मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध जैसा है। वकील ने कहा कि सरकार का आदेश है कि 10 से ज्यादा लोगों को भी इकट्ठा होने के लिए सरकार की मंजूरी लेनी होगी। यह संविधान में दिए गए मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध जैसा है। यहां तक कि अगर किसी पार्क में कोई समारोह होता है तो सरकार के इस आदेश के अनुसार, वह भी अवैध होगा। याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि जब पुलिस कानून लागू है तो फिर ऐसे आदेश की जरूरत क्यों पड़ी सरकार इस तरह के प्रशासनिक आदेश जारी नहीं कर सकती। इस पर राज्य सरकार की तरफ से पेश हुए वकील ने जवाब देने के लिए एक दिन का समय मांगा। इस पर उच्च न्यायालय की धारवाड़ पीठ ने आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी। पीठ ने कहा कि इस आदेश से कर्नाटक सरकार संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (ए) और 19 (1)(बी) के तहत मिले अधिकारों को छीन रही है।

पीएम मोदी ने छठ के समापन पर दी शुभकामनाएं, बोले- दिखी भारत की गौरवशाली परंपरा

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने मंगलवार को चार दिवसीय छठ पर्व के समापन पर श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं दीं और कहा कि इससे देश की भव्य परंपरा की दिव्य झलक देखने को मिली। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर एक पोस्ट में कहा, ''भगवान सूर्यदेव को प्रातःकालीन अर्घ्य के साथ आज महापर्व छठ का शुभ समापन हुआ। चार दिवसीय इस अनुष्ठान के दौरान छठ पूजा की हमारी भव्य परंपरा के दिव्य दर्शन हुए।'' उन्होंने कहा, ''समस्त व्रतियों और श्रद्धालुओं सहित पावन पर्व का हिस्सा बने अपने सभी परिवारजनों का हृदय से अभिनंदन। छठी मइया की असीम कृपा से आप सभी का जीवन सदैव आलोकित रहे। उत्सव शुरू होने से एक दिन पहले, प्रधानमंत्री ने नागरिकों से छठ पूजा के गीतों को साझा करने का आग्रह किया और त्योहार के दौरान उन्हें और भी ज्यादा प्रचारित करने का संकल्प लिया। उन्होंने तीसरे दिन भी ऐसा ही किया, एक गीत साझा किया और अनुष्ठान करने वाले श्रद्धालुओं को शुभकामनाएँ दीं। देश भर में मेरे सभी परिवारजनों को छठ पूजा की संध्या अर्घ्य की हार्दिक शुभकामनाएँ। इस पावन अवसर पर, डूबते सूर्य को अर्घ्य देने की हमारी परंपरा अत्यंत अनूठी है। भगवान सूर्य की कृपा से सभी का कल्याण हो, सभी को जीवन में सुख, समृद्धि और सफलता मिले। यही कामना है। जय छठी मैया। सामुदायिक भागीदारी और ऑनलाइन भक्तिपूर्ण आदान-प्रदान के साथ, इस वर्ष का छठ पर्व एक उज्ज्वल और समावेशी स्वर में संपन्न हुआ, जो इसकी स्थायी सांस्कृतिक प्रतिध्वनि को दर्शाता है।

13 साल के बचे समेत तीन लोगों को यूं खींच ले गई मौत

सारण। बिहार में सारण जिले के अलग- अलग थाना क्षेत्रों में मंगलवार को तालाब में नहाने गए तीन लोगों की डूबने से मौत हो गई। ये हादसे अवतार नगर, गड़खा और परसा थाना क्षेत्रों में हुए। पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, पहला हादसा अवतार नगर थाना क्षेत्र के रामगढ़ा गांव में हुआ, जहां स्नान करने गये श्लोक शर्मा (13), पिता अमरेंद्र शर्मा की मौत तालाब में डूबने से हो गई। दूसरी घटना गड़खा थाना क्षेत्र के फुलवरिया गांव में हुई। यहां मनीष साह के पुत्र साहिल कुमार तालाब में नहाने गए थे। नहाते समय वह गहरे पानी में चले गए और डूबने से उनकी मौत हो गई। तीसरा हादसा परसा थाना क्षेत्र के गोसी गांव में हुआ, जहां नवादा जिले के गोंदपुर थाना क्षेत्र के बेलदारी गांव निवासी लटोपी माली के पुत्र शंभू माली (34) की तालाब में डूबने से मौत हो गई। स्थानीय ग्रामीणों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और तीनों शवों को तालाब से निकालकर सदर अस्पताल भेज दिया गया। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिये जाएंगे। तीनों थाना क्षेत्रों की पुलिस ने अलग-अलग प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।